HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 मई, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 20/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

जीवन की महत्वता सेवा भाव की परख पर ही आंकी जानी चाहिए : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

मौसम का हाल

मौसम इस बार गर्मी का एहसास ही नहीं होने दे रहा है। 1 मई से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंडक महसूस हो रही है । मौसम विभाग की माने तो 4 मई तक बारिश और गर्जन के साथ बादलों की अटखेलियां चलती रहेगी लेकिन उसके बाद मौसम शुष्क हो रहेगा । हालांकि बादलों की आंखमिचौली चलती रहेगी ।

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... हिमाचल खबर
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...कानुन, स्वास्थ्य एवं अन्य
- पृष्ठ 8...संपादकीय: India Faces Leadership Crises
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति: चमक दमक की उड़ान में पंखों की थकान एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की दरकार
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...योजनाएं -हिमाचल पुष्प क्रान्ति, डेयरी एंटरपन्योरशिप
- पृष्ठ 15...स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्त्री स्वाभिमान योजना
- पृष्ठ 16...सर्विस सेवा ऐसोसियेट की भर्तियां....प्रशिक्षण एवं रोजगार

THE RIEV TIMES
OFFICIAL MEDIA PARTNER
krishi & Wellness
INDIA 2019 EXPO
Linking Agriculture, Food & Wellness
06-07-08 August 2019
Pragati Maidan, New Delhi, India

मसूद अजहर घोषित हुआ वैश्विक आतंकी
भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक विजय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत को उस समय बड़ी राजनयिक विजय हासिल हुई जब बुधवार को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। इससे पहले चीन ने उसे प्रतिबंधित करने वाले प्रस्ताव पर लगी रोक को हटा लिया। अजहर पर प्रतिबंध लगने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये, पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर ने कहा कि वह इसे एक 'पक्ष में उठे बहुत बड़े कदम' के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कुछ समय से इसकी कोशिश कर रहा था। चीन इसमें रोड़े अटका रहा था और भारत बार बार इसका प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त गोपालस्वामी पार्थसारथी इसे 'बहुत बड़ी सफलता' के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, 'इससे पाकिस्तान निश्चित रूप से अलग-थलग पड़ेगा। यह सवाल भी है कि क्या (पाकिस्तानी) सेना आतंकवाद का राजकीय नीति के एक तंत्र को तौर पर इस्तेमाल करना बंद करेगी । 'राजदूत विष्णु प्रकाश ने कहा है कि यह अच्छा कदम है लेकिन हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिये क्योंकि वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी खुले आम घूम रहे हैं ।

पंजाब और हरियाणा में गोशाला से जन सेवा तक
रीव फीड सप्लिमेंट और जैविक खाद को मिल रही सराहना
गोसेवकों ने कायम की मिसाल..मिशन रीव का मिलेगा साथ

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

गाय संरक्षण में सरकार के वायदों और मंशा से विपरीत स्थितियां हिमाचल में तो परेशान करने वाली है। लेकिन हिमाचल के बाहरी राज्यों में गो-संरक्षण में नायाब सेवाऐं दी जा रही हैं। द रीव टाइम्स ने जब इसी सिलसिले में पंजाब का दौरा किया और वहां आवारा पशुओं की वास्तविक स्थित का जायज़ा लिया तो इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की पड़ताल हुई। हमने पिछले अंक में बताया था कि मिशन रीव ने पंजाब और हरियाणा में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए रीव जैविक खाद और रीव फीड सप्लिमैंट के सैंपल किसानों एवं गोशालाओं आदि में परीक्षण हेतु दिए जिसके अब सुखद परिणाम सामने आऐ हैं। दरअसल गोशालाओं के संचालक सेवाभाव और पशुधन को ही ध्येय मानकर इनके संवर्धन एवं संरक्षण में समर्पित भाव से सेवाऐं दे रहे हैं जिनके साथ अब मिशन रीव भी संबद्ध होकर सेवाओं को प्रदान करेगा क्योंकि गो सेवा मात्र गो संरक्षण का माध्यम ही नहीं बल्कि वर्तमान में यह सामाजिक आवश्यकता बन गई है । पंजाब में आवारा पशु विशेषकर गाय और बैलों को नाकारा समझकर सड़कों पर छोड़ दिया गया जिससे कुछ समाजसेवी इस विषय पर गंभीरता के साथ आगे आए और इन आवारा गायों आदि के लिए योजनाबद्ध तरीके से कुछ करने की ठानी। इन समाजसेवियों ने आवारा गायों के लिए स्थान का चयन कर आरंभिक चरण में साधारण शैड बनाऐं तथा वहां गायों को रखा। धीरे-धीरे लोगों के सहयोग से इन शैडों को पक्का कर स्थान को बढ़ाया गया। वर्तमान में इन लोगों के प्रयास पंजाब/हरियाणा में उदाहरण बन गए हैं।

गोसेवा के माध्यम से जनसेवा तक का लक्ष्य : महेन्द्र पाल जैन

पंजाब के जमालपुर में गौशाला का संचालन कर रहे महेन्द्र पाल जैन 15 वर्ष पूर्व सड़कों पर लावारिस गायों की दूर्दशा देखकर अपने जीवन को समर्पित भाव से गोसेवा में लगाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए। उन्होंने देखा कि जिन गायों का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, उन्हें दूध न दे पाने के बाद सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। यह अमानवीय कृत्य है और इसके लिए समाज को चिंता करनी चाहिए। इसी सोच के साथ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जमालपुर में एक शमशान घाट के समीप ही ज़मीन लेकर वहां एक शैड बनाकर गोशाला का संचालन आरंभ किया। धन के अभाव में हालांकि यह संभव नहीं था लेकिन आरंभ में हम कुछ ही लोगों ने आपस में ही कुछ चंदा एकत्रित किया और बाद में लोग जुड़ते गए। महेन्द्र पाल सिंह बताते हैं कि उनकी सेवाओं को देखते हुए यहां के पूर्व राज्यसभा सांसद लाला लाजपत ने दो लाख की आर्थिक सहायता की ।

द रीव टाइम्स संपादक हेम राज चौहान के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पास कई नस्लों की गाय और बैल हैं। लेकिन उनका ध्येय हैं कि अपनी देसी नस्ल की गाय का संरक्षण और वृद्धि बहुत ज़रुरी है । इसी उद्देश्य से उन्होंने लुधियाना से बाहर अढाई एकड़ ज़मीन ली जिसमें सिर्फ देसी गायों को रखा, पाला जा रहा है। इनकी संख्या भी अब सैंकड़ों में है। हमारा लक्ष्य है कि देसी गाय जो कि गुणों की खान है, उसका संरक्षण आवश्यक है तथा नई देसी गायों की नस्ल को तैयार किया जाए । उन्होंने गाय को भारतीय संस्कृति का संवाहक बताते हुए कहा कि देसी नस्ल की गाय गुणों की खान है । इसका दूध, दूध से बने उत्पाद, गोबर, गोमूत्र आदि सभी कुछ औषधीय गुणों से संपन्न है । गोमूत्र से अर्क तैयार किया जाता है जिससे कई व्याधियों का उपचार संभव हो पाया है । यह पूछने पर कि इस अर्क को कैसे तैयार किया जाता है, उन्होंने बताया कि गोमूत्र में अजवायन, तुलसी और सौंफ का मिश्रण लेकर इसे तैयार किया जाता है ।

मिशन रीव से मिला गोबर के निष्पादन का तरीक़ा : जैन

महेन्द्र पाल जैन ने बताया कि मिशन रीव के प्रतिनिधि जब पंजाब आए और उन्होंने बताया कि गाय के उपलों का उपयोग जैविक खाद बनाने में बेहतर तरीक़े से हो सकता है। इस बात की हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि गोबर के उपले बनाकर हम उपयोग में लाते थे। अब मिशन रीव के माध्यम रीव जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण लेने पर विचार किया जा रहा है।

रीव फीड सप्लिमैंट के सफल परिणाम आए सामने

मिशन रीव की ओर से सैंपल के तौर पर रीव फीड सप्लिमैंट के उपयोग के बाद गोशाला में दुधारु पशुओं के दुग्ध उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। दूध देने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। महेन्द्र पाल जैन ने बताया कि इसकी सफलता के बाद इसका उपयोग बड़े स्तर पर करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन रीव के इस प्रयास से अन्य गोशालाओं को भी लाभान्वित किये जाने पर विचार होगा। इस गोशाला में किसानों को दुधारु गाय दी जाऐंगी तथा दूध न देने पर वापिस किसान इसे गोशाला में छोड़ सकते हैं ।

भैरो मुन्ना गोशाला का लक्ष्य गोसेवा: रुलदूराम सिंह

15 वर्ष स्थानीय निकायों में सेवाऐं देने वाले रुलदूराम सिंह लोगों की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को बेहतर तरीक़े से जानते और समझते हैं। पंजाब में पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब थी इसी उद्देश्य से उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर 5000 से अधिक वृक्ष न केवल लगाए बल्कि उनका संरक्षण कर मिसाल कायम की। उन्होंने बताया कि पुरातन एवं ऐतिहासिक वृक्षों को यथावत संरक्षित करने में भी सहयोग दिया। वहीं लावारिस गायों की दुर्दशा को देखते हुए गोशाला में इनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की परिचायक देसी गाय के पालन और संरक्षण के लिए ही प्रयास आरंभ किए । देसी बैल से ही शुद्ध देसी गाय की ब्रीड तैयार की गई है । हमारा लक्ष्य है कि देसी गाय के दूध से बनने वाले उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही गाय के गोबर व गोमूत्र से औषधीय उत्पादों को बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

द रीव टाइम्स संपादक से बातचीत में उन्होंने बताया कि दूध देने वाली गायों को किसानों को दिया जाएगा तथा दूध न देने की स्थिति में किसान पुनः उन्हें गोशाला में रख सकते हैं ।

मिशन रीव एक अच्छा प्रयास, उत्पादों से लाभ

रुलदूराम सिंह ने बताया कि मिशन रीव की ओर उन्हें जो भी जानकारी दी गई उससे उन्हें यह मिशन जन सेवा का माध्यम लगा। साथ ही इसके उत्पाद जैसे कि रीव फीड सप्लिमेंट और रीव जैविक खाद भी असरकारक एवं किसानों के लिए उत्साहवर्धक है । क्योंकि इसके उपयोग के बाद इसे सकारात्मक परिणाम सामने आऐं हैं। भविष्य में मिशन रीव के उत्पादों को यहां भी उपयोग में लाये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

1902 में रखी गई थी धर्मार्थ गोशाला की नींव : महावीर सिंह

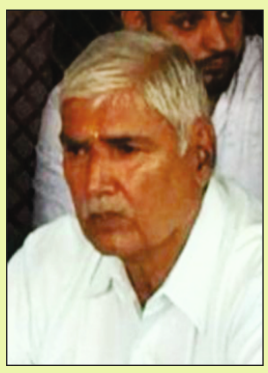

1902 में जिस गोशाला की नींव रखी गई थी आज उसे तीसरी पीढ़ी में लगभग 6000 से अधिक लावारिस पशुओं/गायों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा चुका है। आज यह गोशाला हरियाणा में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत एसीपी धयिया ने अपने जीवन को लावारिस पशुओं की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा गोशाला कमीशन बना रखा है फिर भी सामुहिक प्रयासों एवं जन सहयोग से ही धर्मार्थ गोशाला का संचालन सुचारु रुप से चलाया जा रहा है। इसके लिए एक बड़े बजट की आवश्यकता तो रहती ही है जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा 60 गांवों के लोग भी सहयोग करते हैं। यहां लोगों में सेवा भाव की कमी नहीं हैं और इस धर्मार्थ से 60 से अधिक गांव जुड़ें हुए हैं। धयिया 52 खाफ गांव के प्रधान भी हैं तथा गो सेवा में एक बहुत लंबी कड़ी के रुप में जुड़ें है।

धयिया ने द रीव टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने गोशाला में गायों की अलग श्रेणी बना रखी है जिसमें दूधारु गाय और बांझ गायों को अलग-अलग रखा गया है। गायों की देखभाल और संरक्षण को प्राथमिकता बनाया गया है।

मिशन रीव के लिए पंजाब और हरियाणा में गज़ब का उत्साह : आन्नद नायर

मिशन रीव की ओर से पंजाब और हरियाणा की गोशालाओं में रीव सेवाओं को ले जाने के लिए फ्लायर ग्रुप के सीईओ एवं डायरेक्टर आन्नद नायर और मुकुल सक्सेना सिनियर मार्केटिंग मनेज़र ने दौरा किया। गोशाला के संचालकों के साथ गहन चर्चा की गई तथा रीव फीड सप्लिमेंट का वितरण भी किया गया। इसके अलावा मिशन रीव की सेवाओं को भी खूब सराहना मिली है । गोशालाओं का दौरा इसलिए भी विशेष था क्योंकि रीव जैविक खाद को बनाने और तैयार करने के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। रीव फीड सप्लिमेंट को उपयोग के बाद हरियाणा और पंजाब से सराहनीय परिणाम सामने आने के बाद इसे व्यापक तौर पर वितरण करने व अन्य सेवाओ को वहां ले जाने की योजना पर योजना तैयार की जा रही है ।

स्मार्ट पुलिस के शिमला में गुड़िया की इज्ज़त तार-तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोटखाई गुड़िया कांड के जख़्म अभी सूखे नहीं है और शिमला में एक और गुड़िया इसी तरह की जघन्यता का शिकार हुई है । कमाल तो ये है कि स्मार्ट पुलिस लक्कड़ बाज़ार में जब लड़की अपने साथ होने वाले ख़तरे को भांप कर गुहार लगा रही थी तो ऐसे में उसी स्मार्ट पुलिस के दारोगाओं ने उस लड़की को रात को अकेले बिना कार्यवाही और सुरक्षा के चौकी से भेज दिया। और उसके बाद हुआ वही जिसका डर था। गुड़िया का अपहरण हुआ और रास्ते में उसे उसकी इज्ज़त को तार-तार करने के बाद फेंक दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुद पुलिस को इस वारदात के बारे में लड़की ने फोन कर बताया जिसके बाद ढली पुलिस ने उसे हॉस्पिटल पंहुचाया। यहां सवाल ये है कि क्या गुड़िया कांड की वीभत्सता को सहने के बाद भी हमारी पुलिस को होश नहीं आया और उनकी वर्दी की क्रीज किसी मासूस की इज्ज़त पर भारी पड़ जाती है। सुरक्षा की जिम्मेवारी को निभाने में शिमला की पुलिस अब जनता की नज़रों में अपना रुतबा खोती जा रही है। इंसाफ के लिए सरकार की पहल भी नाकाफी है। ख़बर लिखे जाने तक भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई थी ।

शराब की बिक्री से 1640 करोड़ कमाना चाहती है सरकार

शराब कारोबारियों को बिक्री का दे दिया टारगेट

सरकार के नशा निवारण अभियान पर सवालिया निशान

अंजना ठाकुर, शिमला

नशा निवारण पर प्रदेश सरकार हर साल अभियान चलाती है। जागरूकता के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रूपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन नशे से दूर रहने का राग अलापने के बीच जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी कोश को भरने के लिए सरकार शराब के ही कारोबार को सबसे बड़ा जरिया बनाने पर अमादा है। आबकारी विभाग की नई पॉलिसी इस बात की तस्दीक कर रही है कि सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाना चाहती है और राजकोष को भरना चाहती है। 1 अप्रैल 2019 की आबकारी नीति के मुताबिक प्रदेश में शराब विक्रेताओं पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो शराब बेचने का टारगेट इस बार विक्रेताओं को दिया गया है और अगर वह तय टारगेट से कम शराब बेचते हैं तो उन्हें इसके लिए बाकायदा जुर्माना अदा करना होगा। ऐसे में विक्रेताओं की मजबूरी है कि उन्हें टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी तरह शराब की बिक्री करनी ही होगी। इस बार शराब से सरकार ने 1640 करोड़ रूपये कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि पिछले वित्त वर्श यह 1425 करोड़ था। सूत्रों का कहना है कि गत वर्श भी आबकारी महकमा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहा था।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने नई आबकारी नीति में संशोधन की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि बार संचालकों को आबकारी महकमा राजस्व जुटाने की मशीन समझ रहा है। आबकारी एवं कराधान नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत बार की लाइसेंस फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं सालाना अनिवार्य कोटा 148 पेटी से बढ़ाकर 375 पेटी कर दिया है। इन सब के बीच यह भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाना चाहती है।

शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने प्रेसवार्ता के दौरान आबकारी महकमे की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। एसोसिएशन ने आबकारी नीति के संशोधित प्रावधानों में तुरंत बदलाव की मांग उठाई और ऐसा न होने की स्थिति में प्रदेश भर के करीब 600 बार बंद करने का भी ऐलान कर दिया।

शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि बीते सात सालों में आबकारी महकमे ने लाइसेंस फीस में 700 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। 2013–14 में लाइसेंस शुल्क 55,000 रुपये निर्धारित किया गया था जो 2018–19 के लिए बढ़ाकर 2,50,000 रुपये निर्धारित कर दिया है। इतना ही नहीं पूरे साल की लाइसेंस फीस वसूलने के साथ 10 फीसदी सिक्योरिटी भी साल के शुरू में वसूली जा रही है। इसके अतिरिक्त सालाना न्यूनतम उठान कोटा 2014–15 में 222 पेटी था जिसे 2019–20 में बढ़ाकर 375 पेटी कर दिया है। संजय सूद ने बताया कि बीते साल अधिकतर बार संचालक निर्धारित कोटा नहीं उठा पाया। इसके चलते सभी बार संचालकों को पेनल्टी चुकानी पड़ी। एचपीटीडीसी के होटल ट्रिपल एच और पीटरहॉफ को भी पेनल्टी पड़ी। ऐसे में साफ है कि पूर्व निर्धारित कोटा ही बार संचालकों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है ऐसे में कोटा बढ़ा कर 375 पेटी करना गलत है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम कोटा न उठाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। एक लाख से छह लाख रुपये तक जुर्माने के साथ बार लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया है।

फोरलेन प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करें कंपनियां: हाईकोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन का कार्य जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान क्रमबद्ध तरीके से पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के आदेश पारित किए हैं।

न्यायालय को बताया गया कि किरतपुर-नेरचौक प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 85 किमी है, मगर प्रोजेक्ट का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मुख्य कंपनी और दूसरे प्रभावित पक्षों के बीच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला विचाराधीन है।

ट्रिब्यूनल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए किसी भी तरह का कदम न उठाए। एनएच अथॉरिटी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष इसके आदेशों में संशोधन करने के लिए आवेदन दाखिल कर रखा है। चुनाव आयोग को भी इस बारे में आवेदन किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट बाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नेरचौक पंडोह प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 23 किमी है, लेकिन अभी तक कार्य एक फीसदी पूरा नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि ठेकेदार ने कार्य शुरू ही नहीं किया हुआ है। उसे 87 करोड़ के लगभग एडवांस राशि का हस्तांतरण हो चुका है।

न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि अगर ठेकेदार इस बाबत कोई सही स्पष्टीकरण नहीं देता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यह छूट होगी कि वह उसके कांट्रेक्ट को रद्द करे और नए ठेकेदार को इस काम पर लगाए। न्यायालय ने अगली तारीख तक कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं।

पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 19 किलोमीटर के लगभग है। इसमें चार सुरंग और 14 पुल बनाए जाने हैं। इस काम को 23 सितंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। 31 मार्च 2019 तक करीब 14 फीसदी ही कार्य पूरा हो पाया है।

एनएच अथॉरिटी की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कार्य प्रगति पर है। यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। ठेकेदार की ओर से न्यायालय को यह बताया गया कि कुछ स्थानीय लोग सुरंग के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको उनका पूरा क्षतिपूर्ति मुआवजा जल्द अदा किया जाए।

टकोली – कुल्लू प्रोजेक्ट

एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि प्रोजेक्ट में 28 किमी सड़क का काम 2 जून 2017 को शुरू हुआ था। इसे 29 नवंबर 2019 तक पूरा करने की उम्मीद है। कोर्ट ने एनएचएआई की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि अभी तक इस प्रोजेक्ट का 49 फीसदी काम ही हुआ है और 5 पुलों में से 2 पुल ही बने हैं।

666 निजी निर्माण ऐसे पाए गए हैं जो इस प्रोजेक्ट की जद में आने हैं। इनमें 571 निर्माण हटा दिए गए हैं। कुछ मामलों में मालिकाना हक तय न होने के कारण अधिगृहित निर्माण व भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

कोर्ट ने ऐसे मामलों में स्पष्ट किया कि ऐसे विवाद कब्जा लेने के लिए कोई रुकावट नहीं हो सकते। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की नई समय सीमा सहित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए।

कुल्लू मनाली प्रोजेक्ट

कुल्लू - मनाली प्रोजेक्ट पर एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि इस प्रोजेक्ट में 37 किलोमीटर सड़क का काम 31 मार्च 2019 तक 95 फीसदी पूरा कर लिया गया था। 6 पुलों में से 4 पुल तैयार हैं।

बाकी बचा 5 फीसदी कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा कोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू को आदेश दिए कि वह दो सप्ताह के भीतर भूमि का कब्जा एनएचएआई को दिलवाए।

कोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू सहित पर्यटन विभाग को आदेश दिए कि वह इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाली सड़क पर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को अपना कोई भी काउंटर न लगाने दे।

कोर्ट ने बिजली बोर्ड को भी आदेश दिए कि यदि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान बिजली के खंभों को हटाना है तो उन्हें एक महीने के भीतर हटा दे। मामले पर सुनवाई 26 जून को होगी।

बॉक्सर आशीष ने रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला रजत?

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के आशीष चौधरी ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये फाइनल में कजाकिस्तान के मुक्केबाज से कड़े संघर्ष में हार गए। 26 अप्रैल को थाइलैंड में खेले गए फाइनल में आशीष ने दमदार प्रदर्शन किया। आखिर में प्वाइंट सिस्टम के जरिए कजाकिस्तान के बॉक्सर को विजेता घोषित किया गया। आशीष चौधरी हिमाचल के पहले मुक्केबाज जो एशियन चौंपियनशिप में पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं। वर्तमान में आशीष चौधरी मंडी जिला के धर्मपुर में तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात है।

बॉक्सिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुंदरनगर के कोच नरेश कुमार ने इन्हें प्रशिक्षण दिया है। आर्मी स्पोर्ट्स संस्थान पुणे में हुई 27 अक्तूबर से दो नवंबर तक हुई सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आशीष ने रजत पदक जीता है।

सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड देगा गणित में विकल्प

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

सीबीएसई की तर्ज पर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड बच्चों को गणित के प्रश्न पत्र के लिए विकल्प देगा। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ पर आधारित बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं के लिए दो प्रश्न पत्र तैयार करेगा।

परीक्षार्थियों को इन दो प्रश्नपत्रों में से एक को चुनना होगा। बोर्ड के इस फैसले से उन हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा, जो गणित में कमजोर होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। शुरुआती दौर में मैट्रिक में इसे शुरू किया जाएगा। जबकि इसके सफल परिणाम को देखकर अन्य कक्षाओं में भी शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य प्रश्न पत्रों में भी बोर्ड बदलाव करके 40रू 40रू 20 के अनुपात प्रश्नों की संख्या रखेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी आसान, 40 फीसदी मध्यम दर्जे के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 20 फीसदी प्रश्नों का स्तर ऊंचा होगा। ऐसे में जहां निम्न दर्जे के विद्यार्थियों को पास होने में आसानी होगी और कक्षाओं में ड्रॉप आउट रुकेगा। वहीं मेरिट में वही बच्चे आएंगे, जो उच्च स्तरीय 20 फीसदी अंकों को हल कर सकेंगे। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों की सहूलियत के लिए लिया है। बोर्ड के इस फैसले से निम्न स्तर के बच्चे, जो फेल होने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। उनका स्कूलों से ड्रॉपआउट रूकेगा, जबकि प्रश्न पत्रों में बदलाव से वह बच्चे ही मेरिट में आ सकेंगे, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय तैयारी की होगी।

स्कूल शिक्षा बोर्ड सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में सुधार करेगा। पुस्तकों में शामिल पाठ की रुपरेखा ठीक न होने के कारण उसको पढ़ने और पढ़ाने में निरंतरता नहीं बन पाती है।

हिमाचल में लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षाएं टलीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षाएं आगामी 20 दिन के लिए टाल दी हैं। अब परीक्षाएं 29 मई से शुरू होंगी। पूर्व में ये परीक्षाएं नौ मई से शुरू होनी थीं, लेकिन 19 मई को प्रदेश की चारों सीटों पर लोकसभा चुनाव हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं भी 29 अप्रैल की जगह 8 मई से शुरू होंगी। तकनीकी विवि ने यह निर्णय प्रदेश भर के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

विवि के कुलपति प्रो एसपी बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते विवि ने लिखित और प्रैक्टकल परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। देरी से परीक्षाओं के बावजूद सभी परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित होंगे।

सहायक प्रोफेसर की छंटनी परीक्षा की टॉपर इंटरव्यू में आउट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में करवाई सहायक प्रोफेसर की भर्ती में संगीत विषय वोकल की छंटनी परीक्षा की टॉपर को इंटरव्यू में बाहर कर दिया। आरटीआई से इस संबंध में ली सूचना में टॉपर ने यह खुलासा किया है। अभ्यर्थी अभिलाषा शर्मा ने छंटनी परीक्षा में टॉप किया था, लेकिन वह इंटरव्यू में बाहर हो गई। यही नहीं, परीक्षा के सेकंड और थर्ड टॉपर डॉ. राजेश कुमार, संजय कुमार और मन्नू देवी भी साक्षात्कार की बाधा को पार नहीं कर पाए।

इसके अतिरिक्त रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, आर्टिकल्स और सेमिनार के अंक अन्य राज्यों तथा यूजीसी के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों को मिलने चाहिएं। लोक सेवा आयोग केवल 100 नंबर के साक्षात्कार के आधार पर ही सभी को चयनित कर रहा है जो बिलकुल गलत है।

षर्मा ने लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार से मांग भी की है कि भविष्य में इस नियम को बदलकर अन्य राज्यों की भांति भर्ती प्रक्रिया की जानी चाहिए। कुछ समय पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी 100 अंक के साक्षात्कार के नियम को बदला है। राज्य लोक सेवा आयोग की सचिव के मुताबिक आयोग सहायक प्रोफेसरों की छंटनी परीक्षा के अंक नहीं जोड़ता है। साक्षात्कार सौ अंक का होता है और इसके आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों का चयन होता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कलनेरी प्रतियोगिता में एपीजी के स्टूडेंट्स ने जीता सोना
मौकटैल व स्टूडेंट शैफ प्रतियोगिता में झटके गोल्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल कलनेरी प्रतियोगिता में स्थानीय अलख प्रकाश गोयल (एपीजी) शिमला विश्वविद्यिलय के होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रेस सलाहकार सत्यदेव शर्मा ने बताया कि होटल होली-डे होम में पर्यटन विभाग तथा हिमाचल शैफ एसोसिएशन द्वारा करवाई गई कलनेरी प्रतियोगिता में मौकटेल स्टूडेंट तथा स्टूडेंट शैफ वर्ग की तीनों कैटागिरी में अव्वल स्थान अर्जित किया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की अलग-अलग विश्वविद्यालयों के करीब 50 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। शर्मा ने बताया कि मौकटेल स्टूडेंट स्पर्धा में विश्वविद्यालय की सोनम-की-लेचंपा और शुभम साहु ने गोल्ड जीता। इसी स्पर्धा में अमनीत अली व मन्नत शर्मा ने सिल्वर जीता तथा निशांत ने ब्राऊन का तडका लगाया। जबकि अमर नाथ और बीरेंद्र शर्मा मैरिट में रहे। सत्यदेव शर्मा ने बताया कि हिमाचल कलनेरी प्रतियोगिता की स्टूडेंट शैफ स्पर्धा में शुभम शर्मा और संतोष कुमारी ने गोल्ड जीता। रजत कुमार झा ने सिल्वर तथा दीपू व नरेश कुमार ने ब्राऊन लेकर विश्वविद्यालय का स्थान ऊंचा किया। इस स्पर्धा में भी अमरनाथ ने मैरिट में जगह बनाई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसएन कुलकर्णी ने हिमाचल कलनेरी प्रतियोगिता में अव्वल स्थान अर्जित करने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्तापर्क शिक्षा देने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राजधानी में हुई इस महत्वपूर्ण स्पर्धा में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने साबित किया है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के प्रतिष्ठित होटल व्यवसाय से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनके समक्ष हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट संकाय के विभागाध्यक्ष चेतन मेहता ने बताया कि हिमाचल कलनेरी प्रतियोगिता में हमारे स्टूडेंट्स ने आशानुरूप प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने बेहतर प्रदर्शन करके हमारा तथा विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर होटल मैनेजमेंट के विधित चौहान, शैफ गौतम, नैंसी, कमल, सुमन, वैभव तथा पवन उपस्थित रहे।

मशोबरा का उप-रोजगार कार्यालय स्वयं बेरोजगार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मशोबरा में उप-रोजगार कार्यालय में सरकार की अनदेखी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोजगार कार्यालय में सैंकड़ों बेरोजगार युवाओं की लंबी लाईनें प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों हेतु लगी रहती हैं और स्टाफ के नाम पर केवल एक रोजगार अधिकारी की वर्तमान में तैनाती है। एक अधिकारी होने के कारण यहां कार्य निश्पादन में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस उप रोजगार कार्यालय में एक पद जुनियर एसिसटैंट का था जो वर्तमान में क्षेत्रिय रोजगार कार्यालय में अटैच है और एक पद डेटा एंट्री ऑपरेटर का है जो कि मेडिकल अवकाश पर है। इससे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक अधिकारी के पास लंबी-लंबी लाईने लगी हुई है और स्टाफ के नाम पर सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है।

इस उप रोजगार कार्यालय में कौशल विकास के प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेज़ों की उपलब्धता के साथ-साथ रोजगार का पंजीकरण, नवीनीकरण, सरकारी एवं निजी व्यवसाय के लिए पंजीकारण, बेरोजगारी भत्ता आदि समस्त आवश्यक कार्यों को निष्पादन होता है। इससे यहां बेरोजगार युवाओं की भीड़ रहती है। उद्घोष संस्था ने इस पर नाराजगी ज़ाहिर की है तथा सरकार को कोसते हुए मांग की है कि तुरंत कार्यालय में कर्मचारियों को वापिस बुलाया जाए जिससे युवाओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। उद्घोष संस्था के चेयरमैन हेम राज चौहान ने बताया कि संस्था ने मौका पर जाकर स्थिति का जायज़ा लिया और इस विषय पर वहां कतारों में खड़े युवाओं से भी बात की। पंजीकरण के लिए लाईन में खड़े बेरोजगार युवा सूरज वर्मा ने बताया कि मशोबरा में उन्हें इस कार्यालय में कई चक्कर लगाने पड़े हैं तथा यहां स्टाफ न के बराबर है जिससे हमें असुविधा होती है। उद्घोष ने मांग की है कि यहां वहां अटैच किए कर्मचारियों को तुरंत कार्यालय में बिठाया जाए और जो पद रिक्त हैं उन्हें भरा जाए ताकि रोजगार कार्यालय की बेरोजगारी दूर की जा सके। संस्था ने इस बाबत एक पत्र संबन्धित मंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखा है।

खटनोल स्कूल में दो साल से नहीं कामर्स -साइंस के अध्यापक

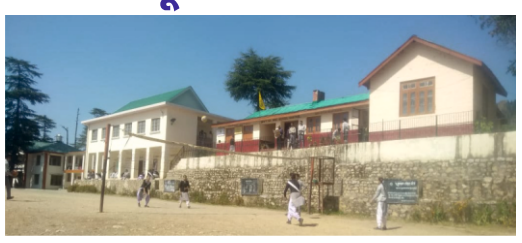

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजकीय माध्यमिक पाठशाला खटनोल में बीते दिनों विद्यालय प्रबंधन की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता एसएमसी गीता शर्मा और स्कूल प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने की। आम सभा की कार्यकारिणी के सदस्य नरेश दयोग, उशा ठाकुर, धर्मेंद्र ठाकुर, देवी सरण और अध्यापक वर्ग में राजेंद्र कृष्ण, गायत्री दत्त शर्मा और जसवीर कौर आदि सभा के दौरान उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान गत वर्ष के दौरान आयोजित शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान अभिभावकों ने स्कूल में खाली पड़े प्रवक्ताओं का मामला भी उठाया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में प्रवक्ताओं के पद खाली होने के कारण अपेक्षित परीक्षा परिणाम नहीं मिल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। खटनोल स्कूल में भौतिक विज्ञान, रसायन व वाणिज्य के अध्यापकों के पद खाली हैं। इसके कारण यहां पर इन विषय में छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले दो सालों से इन विषयों के अध्यापक स्कूल में नहीं है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि इस बारे में कई बार सरकार को अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। अभिभावकों का कहना है कि अगर जल्द स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ेगा जहां पर पूरे अध्यापक हो। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि एक बार दोबारा सरकार और विभाग को स्कूल में खाली पड़े पदों से अवगत कराएंगे और पदों को जल्द भरने की मांग की जाएगी।

मौसम बिगड़ने से सेब की बंपर पैदावार पर संकट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देश में खराब मौसम से सेब की बंपर पैदावार की उम्मीद टूट रही है। कहीं बारिश, तूफान तो कहीं ओलावृष्टि से बागवानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। निचले क्षेत्रों के सेब बहुल क्षेत्रों में अंधड़ और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट से फसल प्रभावित होने के आसार बन रहे हैं।

मौसम के बिगड़ते मिजाज से प्रदेश में चार हजार करोड़ के प्रत्यक्ष और परोक्ष सेब के कारोबार पर असर पड़ सकता है। हाल ही में गिरे ओलों से रामपुर के ऊंचे इलाकों में फ्लावरिंग स्टेज पर ही सेब फसल तबाह हो चुकी है। ओलों से सेब के फूल सहित बीमे पेड़ों से उखाड़कर जमीन पर गिर गए हैं।

डीडीयू में पानी की कमी के कारण टालने पड़े ऑपरेशन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जोनल अस्पताल डीडीयू में बुधवार को पानी न होने के कारण अहृपरेशन टालने पड़े। अस्पताल से 3 गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन करवाने के लिए कमला नेहरू अस्पताल रेफर करना पड़ा। बाकी ऑपरेशन भी नहीं हो पाए। दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में बुधवार सुबह पानी की कमी हो गई और अस्पताल प्रबंधन को ऑपरेशन तक टालने पड़े।

अस्पताल में औसतन 10 से अधिक आर्थो सर्जरी, गायनी के ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन पानी की सप्लाई न होने के चलते सभी ऑपरेशन रुक गए बताया जा रहा है कि लोअर बाजार में दो जगह से पाइप के फटने के चलते सप्लाई बाधित हो गई थी।

गडकरी ने शिमला से माओवादियों को दी चेतावनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

तबीयत बिगड़ने से पहले केंद्रीय भूतल परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने दो ट्वीट किए। किन्नौर के सांगला में जनसभा से लौटने के बाद गडकरी ने शिमला के छराबड़ा में होटल वाइल्ड फ्लावर हाल से 4.27 बजे ट्वीट किया।

उन्होंने लिखा-- गढ़चिरौली में हमारे सुरक्षा बलों पर किए माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। माओवादियों को इस कायराना हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

लोकसभा चुनावः छंटनी में नौ नामांकन रद्द अब चुनाव मैदान में इतने उम्मीदवार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनकी स्क्रूटनी हुई। कवरिंग कैंडीडेट समेत नौ आवेदकों के नामांकन रद्द हुए। प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के लिए कुल 55 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे।

अब 46 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मंडी सीट से 17, कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 11-11 और शिमला से 7 उम्मीदवार शामिल हैं।

जिन उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हुए हैं, उनमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के कवरिंग कैंडीडेट धर्मेंद्र सिंह पटियाल, भाजपा के प्रवीण शर्मा और स्वाभिमान पार्टी के राजेश कुमार के अलावा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार प्रताप सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के कवरिंग कैंडीडेट प्रकाश चौधरी, भाजपा के खुशाल चंद ठाकुर, राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी के बली राम, निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र कुमार और शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के कवरिंग कैंडीडेट अमित नंदा का नामांकन रद्द हो गया है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो मई निर्धारित है।

शिमला दुष्कर्म मामले पर हिमाचल में सियासत गर्म, सड़कों पर कांग्रेसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बुधवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने मामले पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर, भाजपा ने कांग्रेस पर इस मामले में सियासत करने का आरोप लगाया है। शिमला दुष्कर्म मामले पर बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में धिक्कार दिवस मनाया।

जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश की जयराम सरकार को हटाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे। प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सरकार इस गंभीर मामले में लीपापोती कर रही है।

रिज टैंक को बचाने की कवायद, शिमला पहुंची बेल्जियम और दिल्ली की कंपनियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ऐतिहासिक रिज मैदान पर हो रहे धंसाव के चलते स्टोरेज टैंक को पैदा खतरे का समाधान निकालने के लिए दो कंपनियां शिमला पहुंच गई हैं। यह कंपनियां अगले दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेयजल कंपनी को देंगी। बुधवार को भी इन कंपनियों की टीमों ने रिज मैदान का जायजा लिया। पेयजल कंपनी के अनुसार निरीक्षण पर आई एक कंपनी एडी कोज बेल्जियम की है जबकि दूसरी शिल्पी टेक नई दिल्ली की है।

बुधवार को इन टीमों के विशेषज्ञों ने टैंक के अलावा रिज के उन हिस्सों का भी निरीक्षण किया है जिनके लगातार धंसने से रिज मैदान को खतरा पैदा हो गया है। लक्कड़ बाजार और रिवोली वाले हिस्से में लगातार धंसाव के चलते टैंक को भी खतरा पैदा हुआ है। रिज टैंक में पड़ी दरारें भरने के लिए पेयजल कंपनी ने ऐसी फर्मों को टेंडर देने की तैयारी की है जिन्हें पहले भी इस तरह के काम का अनुभव हो। इसलिए कंपनियों को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। अभी दो कंपनियां शिमला पहुंची हैं।

रिज टैंक की छत और दीवारों में पड़ी हैं दरारें

टैंक की छत और दीवारों में बड़ी दरारें पड़ने से रिज टैंक को खतरा पैदा हो गया है। यह दरारें साल 2018 में टैंक की सफाई के दौरान पहली बार देखी गई थी। लेकिन छत से शुरू हुई ये दरारें अब दीवारों पर भी देखी जा सकती हैं। हालांकि, पेयजल कंपनी दावा कर रही है कि अब दरारें स्थिर हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर इसे भरना जरूरी है। इसीलिए कंपनियां बुलाई जा रही हैं। टैंक पर रैलियां करने पर भी रोक लगाने की मांग की है। पेयजल कंपनी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल का कहना है कि दो कंपनियों ने संपर्क किया है। इनके प्रपोजल देखने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।

नेशनल हाईवे पर फिर दरका पहाड़, यातायात बाधित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ढली टनल भट्टाकुफर बाईपास पर शिवमंदिर के पास बुधवार शाम ने नेशनल हाईवे-5 पर अचानक पहाड़ी से बड़े-बडे पत्थर गिर गए। गनीमत यह रही कि पत्थरों की चपेट में कोई वाहन नहीं आया। पत्थर गिरने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही थम गई।

पहाड़ के दरकने से करीब एक घंटे तक नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक वन-वे रहा। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी ट्रैफिक कमल वर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जेसीबी से सड़क साफ करने के निर्देश दिए।

तीन सितंबर 2017 को भी शिव मंदिर के पास पहाड़ दरक गया था। भारी भूस्खलन से सड़क किनारे खड़े वाहन खाई में गिर गए थे। शिव मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन ने भूस्खलन रोकने के लिए स्थायी इंतजाम के दावे तो किए लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।
द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334, Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बजरंग अखाड़ा में कुश्ती और जूडो में पारंगत होंगे खिलाड़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, (सोलन)
औद्योगिक हब बीबीएन के युवक-युवतियां बजरंग अखाड़े में कुश्ती और जूडो में पारंगत बन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। नालागढ़-रोपड़ मार्ग पर जगातखाना में श्रीबजरंग अखाड़ा खुल गया है जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजरंग अखाड़ा के अध्यक्ष अजय कुमार अजू और वरुण नेगी बोनी ने कहा कि अखाड़े में खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि आर्थिक स्थिति अच्छी न होने वाले खिलाड़ियों को निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी।

गाड़ी धोने और बागीचों में पानी की बर्बादी पर नजर रखेगा विभाग
गर्मियों में हांफ जाती हैं पेयजल और सिंचाई की योजनाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो
गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सोलन में आईपीएच विभाग ने एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। विभाग ने साफ किया है कि अगर कहीं पर पानी की बर्बादी हुई तो तुरंत पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
गर्मी में लोगों को पेयजल किल्लत से बचाने के लिए आईपीएच विभाग तैयारियों में जुट गया है। आईपीएच महकमे ने बाकायदा एक्शन प्लान बनाकर इसे लागू कर दिया है। पानी का जरा सा भी दुरुपयोग किया तो तुरंत ही संबंधित व्यक्ति का पेयजल कनेक्शन कट जाएगा। विभाग ने गर्मियों में पेयजल की भारी किल्लत के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। अभी गर्मी ने दस्तक ही दी है कि 25 फीसदी पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है। विभाग के मुताबिक गाड़ियां धोना, बगीचों में पानी डालना आदि पर पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में विभागीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और टीमों का गठन कर अधिकारियों व कर्मियों की ड्यूटियां बनाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुबह व शाम के समय टीम विशेष रूप से निगरानी रखेगी। इसके अलावा विभाग ने लीकेज रोकने के लिए मरम्मत कार्य भी चला रखा है ताकि पानी की बर्बादी न हो सके। एक्सईएन आईपीएच नालागढ़ मंडल के मुताबिक गर्मियों में पेयजल समस्या से निपटने के लिए विभाग तैयार है। यदि कोई पानी का दुरुपयोग करता पाया गया तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे पानी को व्यर्थ न बहाएं।

कुनिहार में किसानों की आलू की फसल रोग की चपेट में

द रीव टाइम्स ब्यूरो , सोलन
कुनिहार विकास खंड के तहत स्यारी कंडला गांव के किसानों की आलू की फसल में बीमारी लगने से चिंता बढ़ गई है। किसानों को अब आलू की बेहतर कीमत मिलने की संभावना कम होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि किसानों ने कुनिहार कृषि विभाग कार्यालय से 32 रुपये किलो के हिसाब से आलू का बीज लिया था। इसे उन्होंने 8 से 10 बीघा जमीन पर जनवरी माह में रोपा था। अब खेतों में आलू के तनों पर काला दाग लगना शुरू हो गया है। पौधा गल कर टूट रहा है। इससे किसानों को अच्छी उपज होने की संभावना खत्म हो रही है। साथ ही हजारों रुपये का बीज खेतों में लगा कर रोडोमिल स्प्रे करने के बाद भी पौधों में लगी इस बीमारी से निजात न मिलने से किसानों को चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि उनका जीवन-यापन नकदी फसलों पर ही निर्भर है। दुर्गा सिंह का कहना है कि करीब 20 हजार का बीज लगाया था जो तने में लग रहे रोग के कारण फसल खराब होने लगी है।
एसएमएस कुनिहार कृषि विभाग मनोज शर्मा ने बताया कि किसानों को खराब हो रही फसल का सैंपल कार्यालय लाने के लिए कहा गया है। अगर रोडोमिल स्प्रे से कोई असर नहीं हो रहा है तो किसान सेप्टरो साइकलिन स्प्रे करें। तापमान बढ़ने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से बात कर समस्या का निदान जल्द किया जाएगा।

वोट प्रतिशत बढ़ाने में बेहतर प्रदर्शन पर बीएलओ होंगे सम्मानित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन
लोकसभा चुनाव के तहत 19 मई को वोटर टर्न आउट बढ़ाने की दिशा में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के प्रयासों को अवार्ड से पहचान दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि सोलन के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जिस मतदान केंद्र में सर्वाधिक मत प्रतिशत रहेगा, उस मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को अवार्ड दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि इन पांच के अलावा जिला स्तर पर भी एक अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड को सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल बूथ लेवल अधिकारियों में से उस अधिकारी को दिया जाएगा जिसकी मत प्रतिशतता सबसे अधिक रहेगी। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

धर्मपुर में मिस्त्री के बैंक खाते से शातिरों ने उड़ाए 94 हजार

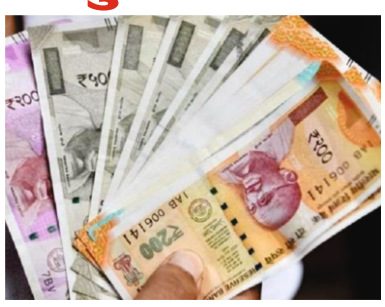

द रीव टाइम्स ब्यूरो , सोलन
धर्मपुर में एक मिस्त्री के पीएनबी खाते से शातिरों ने 94 हजार रुपये की राशि पर हाथ साफ कर लिया। शातिरों ने इस व्यक्ति का एटीएम प्रयोग कर उसका पिन नंबर जानने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। मामला 12 अप्रैल का है जबकि पीड़ित व्यक्ति को इस बात का पता 16 अप्रैल को बैंक खाते की जांच करने के बाद चला। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत धर्मपुर थाना में दर्ज करवाई है।
पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कमलेश कुमार सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह निवासी गांव दाह डाकघर भाटावाला तहसील और थाना बहादुरगंज जिला किशनगंज बिहार जो हाल में गांव बाडा कुमारहट्टी सोलन में किराये के कमरे में रह रहा है, सोलन सहित आसपास के क्षेत्र में मिस्त्री का काम करता है, ने पुलिस को शिकायत दी कि वह जब 11 अप्रैल को चौहान कांप्लैक्स कुमारहट्टी में पीएनबी के एटीएम से पैसे निकालने गया था लेकिन कार्ड डालने पर एटीएम से पैसे नहीं निकले रह थे।
वहीं एटीएम में पहले से तीन-चार लड़के मौजूद थे। इसमें से एक लड़का बोला कि तुम्हारे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे और कहा कि साथ वाला लड़का उसके एटीएम से पैसे निकाल देगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपना एटीएम मौजूद एक लड़के को दिया और अपना पिन नंबर भी उसे बता दिया और 20 हजार रुपये निकाले। उसके बाद उसने 12 अप्रैल को फिर से ओरियंटल बैंक के एटीएम कुमारहट्टी से खुद छह हजार निकाले।
इसके बाद उसके खाते में 12 अप्रैल तक 1 लाख 10 हजार 282 रुपये बच गए थे। उक्त व्यक्ति 16 अप्रैल को जब अपनी पासबुक में एंट्री करवाने गया तो उसके खाते से एक साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने 94 हजार की राशि पर हाथ साफ कर दिया था। उसके खाते में सिर्फ 15 हजार 988 रुपये बकाया रह गया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

एएसपी सोलन शिव कुमार ने बताया कि पुलिस थाना धर्मपुर में 420 का मामला दर्ज किया गया है। इसमें पीड़ित व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बैंक खाते से 94 हजार पर हाथ साफ करना बताया है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। पुलिस एटीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है।

क्लोरीनेशन के बाद ही हो पानी की सप्लाई
जिला स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन
जिला स्वास्थ्य विभाग ने हिमुडा और आइपीएच विभाग को निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि पेयजल योजना के टैंकों की साफ-सफाई कर क्लोरीनेशन के बाद ही पानी की सप्लाई की जाए। यह निर्देश परवाणू में डेंगू, मलेरिया सहित अन्य जलजनित रोगों की रोकथाम को लेकर आयोजित बैठक में दिए गए। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त परवाणू डॉ. विक्रम सिंह नेगी ने की। जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता, ईएसआई अस्पताल के कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनोद कपिल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अल्पना, डॉ. कविता, परवाणू नगर परिषद के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन, इस बार बदलते मौसम को देखकर डेंगू का जल्दी प्रकोप बढ़ सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को डेंगू को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
गौर हो कि पिछले वर्ष डेंगू के जिला भर में 1695 मामले सामने आए थे। अकेले परवाणू क्षेत्र में सबसे अधिक 1098 मामले सामने आए थे। 403 ऐसे मामले थे, जो अन्य राज्य के लोगों द्वारा हिमाचल में टेस्ट करवाने पर पाए गए थे। वहीं, बद्दी में डेंगू के 409, नालगढ़ में 102, सोलन में 73 और सुबाथू क्षेत्र में डेंगू के 13 मामले सामने आए थे।

किसी सरकार ने नहीं ली पांवटा-फेडिज एनएच की सुध

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर
प्रदेश और केंद्र में कई सरकारें बनीं और बदल गईं लेकिन, सिरमौर जिले के दुर्गम शिलाई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले पांवटा-फेडिज नेशनल हाईवे 707 की आज तक सुध नहीं ली गई। इस सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। शिलाई के उपमंडल मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है। शिलाई पहुंचने के लिए लोगों को गाड़ियों में हिचकोले खाने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
हालत यह है कि सड़क पर मैटलिंग के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं। सड़क पर वाहनों का चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। इससे वाहन चालकों के साथ-साथ यात्रिओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क की लंबाई पांवटा से फेडिज तक 108 किलोमीटर है। सड़क पर दो चरणों में मैटलिंग की जानी थी। पहले चरण में पांवटा से बोहराड़ तक 50 किलोमीटर का कार्य हुआ लेकिन, दूसरे चरण में बेहराड़ से फेडिज पुल तक 12 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी सड़क की हालत नहीं सुधरी।

जिले के 71 स्कूलों के सभी शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना
चुनाव आयोग ने जिले के 71 स्कूलों के सभी शिक्षकों की चुनावी ड्यूटियां लगाई हैं। इनमें ऐसे स्कूलों की संख्या ज्यादा है जहां एक या दो शिक्षक ही तैनात हैं।
ड्यूटी में तैनात शिक्षकों की पहली रिहर्सल जिला में हो चुकी है। उनकी दूसरी रिहर्सल 6 और 7 मई को होगी। इसके बाद 15 मई से चुनाव खत्म होने तक शिक्षकों की पोलिंग बूथों पर ड्यूटी रहेगी। कई स्कूलों में तो सेवादारों के पद भी खाली हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि जिन स्कूलों में स्टाफ ही नहीं रहेगा वहां बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
गौरतलब है कि अभिभावक सरकारी स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर पर, खाली पदों को लेकर पहले से ही परेशान हैं। शेष शिक्षकों की भी चुनावों में ड्यूटी से अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। जिला में 71 सरकारी स्कूलों में 23 स्कूल ऐसे हैं, जो मात्र एक शिक्षक के सहारे है। इसके साथ 48 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक ही उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग की ओर से इन शिक्षकों की भी ड्यूटियां चुनाव में लगा दी है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटियां चुनाव में लगाई है, उनमें डेपुटेशन शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए बीईईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे स्कूलों में शिक्षा का व्यवस्था बनी रहेगी।

घासनी को आग लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना
गर्मी के सीजन में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वन विभाग की टीमें इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं।
हाल ही में वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी रामगढ़ खरवाईं के रेंज ऑफिसर रशपाल सिंह, बीओ अजीत सिंह राणा एवं कर्मचारियों की टीम ने अमरोह बीट में ग्रामीणों को जागरूक किया।
वन परिक्षेत्र अधिकारी खुरवाईं रशपाल सिंह ने कहा कि मलकीयती या घासनी की साफ सफाई के बाद यदि आग लगानी है, तो उसकी सूचना वनरक्षक, वन खंड अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर को देना आवश्यक है और अनुमति लेना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मलकीयत या घासनी में बिना सूचना और बिना अनुमति के आग लगाता पकड़ा जाता है, तो उसे प्रदेश वन अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये प्रति कनाल का जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जंगल में आग लगाता पकड़ा जाता है, तो उसे भारतीय अधिनियम 1927 के तहत सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं।
बीओ अजीत सिंह राणा ने लोगों का आह्वान किया है कि यदि निकटतम क्षेत्र में कहीं भी आग लगी दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम रेंज ऑफिसर पर तुरंत दें। इस अवसर पर उनके साथ बीओ अजीत सिंह राणा, फॉरेस्ट गार्ड अजय व ग्राम वासी उपस्थित रहे।

भाई को बचाने के लिए भेजा चौपार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर
चूड़धार की यात्रा पर निकले युवक और युवती ने तीन दिन और दो रातें भूखे पेट गुजारीं। दोनों अपने साथ खाने के लिए कुरकुरे और चिप्स लेकर गए थे। इसमें तीन पुलिस के जवान, दो वन कर्मचारी, चार राजस्व विभाग के कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण शामिल था। सिरमौर पुलिस ने शिमला पुलिस से संपर्क किया तो वहां से भी एक रेस्क्यू टीम चोटी की ओर निकली। लेकिन, दुर्गम पहाड़ी पर फंसे होने के कारण टीम उस तक नहीं पहुंची। रितेश के भाई देवेंद्र सिंह ने दिल्ली की एक कंपनी का निजी चौपर हायर किया और देहरादून से चूड़धार के लिए उड़ान भरी। दोपहर बाद युवक और युवती दोनों को ट्रेस किया गया। लेकिन, उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका। करीब आधा घंटे बाद रस्सियां फेंककर दोनों को हेलीकॉप्टर में देहरादून पहुंचाया गया। दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। एसडीएम राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

फिलहाल चूड़धार की यात्रा पर न जाएं लोग : राहुल कुमार

एसडीएम राहुल कुमार ने बताया कि चेकपोस्ट का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फिलहाल चूड़धार की यात्रा पर न जाएं। जबकि प्रतिबंध हटने के बाद भी मौसम की स्थिति को भांप कर ही यात्रा पर जाना चाहिए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिले की सीमाएं सील, हर नाके पर लगाई पुलिस प्रवेश द्वारों पर 50 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

लोकसभा चुनाव के चलते कांगड़ा पुलिस ने जिला के सीमांत क्षेत्रों पर चौकसी बढ़ा दी है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने कहा कि चुनावों में अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए पंजाब सीमा से सटे कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को सील कर दिया गया है। पुलिस थाना इंदौरा और पुलिस थाना डमटाल के तहत 10 प्रवेश द्वारों पर 50 पुलिस कर्मचारियों को जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा बीडीओ सर्विसलेस टीमों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंडवाल और अन्य बैरियरों की सुरक्षा के चलते पुलिस बल तैनात कर दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र छन्नी बैली, माजरा, भदरोया, तोकी, बरोटा, ठाकुरद्वारा, मीलवां, गगवाल, डमटाल, काठगढ़, पराल के 10 अंतरराज्यीय नाकों पर पांच-पांच पुलिस कर्मचारी तैनात किए हैं। उन्होंने बताया कि थाना इंदौरा थाना डमटाल, पुलिस चौकी कंडवाल के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर संदिग्ध वाहनों कार, मोटरसाइकिल, कैंटर, बसों की पूरी चेकिंग करें।

कक्ष और पार्किंग में लगाएं सीसीटीवी पुलिस ने होटल कारोबारियों को दी हिदायत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

कांगड़ा पुलिस ने पर्यटन सीजन में सभी होटल कारोबारियों को कोई हिडन चार्ज न लेने की हिदायत दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला के सभागार में जिला के होटल कारोबारियों के साथ एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने बैठक की। उन्होंने सभी होटल कारोबारियों से स्वागत कक्ष, पार्किंग और होटल के खुले परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की पूरे देश में छवि है, यहां शांति है। ऐसे में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग ऐसे स्थानों की ओर रुख कर सकते हैं, जो बाद में बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाद में कई बार जांच में आता है कि आरोपी हिमाचल में कई दिन तक रह चुका है। जिसकी किसी को भनक तक नहीं लग पाती है। ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए पार्किंग और स्वागत कक्ष में सीसीटीवी कैमरे होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे जो भी चार्ज करते हैं, उसके बारे में पहले ही पर्यटक को बताया जाए। इस मौके पर एएसपी दिनेश कुमार, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी बांबा सहित अन्य होटल कारोबारी मौजूद रहे।

नशे पर लगाम लगाने के लिए करें सहयोग

पुलिस ने होटल कारोबारियों से चिट्टा और चरस बेचने वालों को पकड़ने में सहयोग मांगा है। इसके अलावा होटल की बार नियमों के अनुसार चलाने की सलाह दी। वहीं, देह व्यापार का कोई संदिग्ध लगे, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

पुलिस ने होटल कारोबारियों से हर पर्यटक से पहचान पत्र लेने का आह्वान किया। इसके अलावा होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी कार्य देने से पहले दस्तावेजों की जांच करवा लें। किसी अन्य एंजेसियों से बुकिंग करवाकर पर्यटकों को होटल में न ठहराएं।

12 साल में नहीं बन पाया स्वारघाट पर्यटन सूचना केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

सूबे में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए स्वारघाट में बनने वाला पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण 12 सालों से अधर में लटका हुआ है। इसका शिलान्यास 12 सितंबर 2007 को तत्कालीन मंत्री रहे रामलाल ठाकुर ने किया था। इसके लिए 50 लाख रुपये का बजट भी स्वीकार किया जा चुका था लेकिन दशक बाद भी पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

यह पर्यटन सूचना केंद्र प्रदेश में पहुंचने वाले सैलानियों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया था लेकिन सूचना केंद्र न बनने के कारण आज भी प्रदेश में पहुंचने वाले सैकड़ों सैलानी इस सुविधा से महरूम हैं।

हालांकि पर्यटन विभाग की तरफ से पहली किस्त के रूप में 25 लाख की राशि भी उस दौरान जारी करते हुए वन विभाग को पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण करने के लिए सौंपी थी। इसके बाद वन विभाग ने पर्यटन सूचना केंद्र के भवन का निर्माण कार्य शुरू करते हुए करीब साढ़े तेरह लाख खर्च भी कर दिए हैं लेकिन 16 पिल्लर बनाकर उस पर छत डालने से आगे कोई कार्य नहीं हो पाया।

नेशनल हाईवे चंडीगढ़-मनाली सड़क पर हिमाचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले स्वारघाट कस्बे में पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण होने से कुल्लू-मनाली व शिमला समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से घूमने आने वाले पर्यटकों को विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान होना था।

हमीरपुर में एचआरटीसी के दस बस रुट बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

हिमाचल पथ परिवहन निगम का हमीरपुर डिपो बस चालकों और परिचालकों की भारी कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी से इस समय अकेले जिला हमीरपुर में ही करीब दस बस रूट बंद हो चुके हैं। ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसों के बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पिछले कई वर्षों से चल रहे पुराने रूट भी कई दिनों से बंद हैं।

मैहरे से शाहतलाई वाया दियोटसिद्ध -हमीरपुर बस रूट पिछले लगभग दो हफ्तों से बंद है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं और इलाके के लोग मजबूरन महंगी दरों पर टैक्सियों के जरिये सफर करने को मजबूर हैं। क्षेत्र के बब्बी शर्मा, नवजोत शर्मा, मनजीत कुमार, सलोचना और हुकमी देवी का कहना है कि बस रूट बंद होने से टैक्सी चालकों को मनमाने पैसे देने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार और परिवहन निगम से तुरंत बस सेवा बहाल करने की मांग की है। उधर, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि वर्तमान में शादियों के सीजन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैहरे, शाहतलाई, दियोटसिद्ध, हमीरपुर बस रूट को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा।

करोड़ों रुपये के घोटाले पर सभा की गई भंग, सचिव को हटाने के आदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

विकास खंड झंडूता के तहत आने वाली दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में सहायक पंजीयक अधिकारी ने सभा को भंग कर दिया। जबकि सभा के संचालन के लिए सभा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वहीं नई सभा कार्यकारिणी को आदेश दिए गए हैं कि वह सभा सचिव को उनके पद से निलंबित करें। जांच में पाया गया है कि 32, 71, 90, 269.50 करोड़ का गोलमाल सभा की लापरवाही के कारण हुआ है। वहीं इस संबंध में पुलिस भी भादंसं की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। उल्लेखनीय है कि जिला अंकेक्षण अधिकारी व जिला निरीक्षक सहकारी सभाएं बिलासपुर द्वारा 14 मार्च 2019 को दी गई अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया । गबन के आरोप में 16 मार्च को एफआईआर दर्ज करवाई गई। तत्कालीन प्रबंध कमेटी की संलिप्तता व लापरवाही सामने आने के कारण कमेटी को विभाग की ओर से मुक्त कर दिया गया है और कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। जिला सहायक पंजीयक अधिकारी द्वारा कानूनी धारा कोऑपरेटिव एक्ट 35 ए के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

सहायक पंजीयक अधिकारी रमेश चंद शर्मा के मुताबिक जैसे ही उन्होंने जिला का कार्यभार संभाला तो उन्हें पता चला कि तलाई सभा में सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार चल रहा है लेकिन मुनाफा मात्र एक लाख बताया जा रहा है। इस पर उन्हें इसमें गड़बड़ी होने का संदेह हुआ जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन की गई तो पाया गया कि करीब 33 करोड़ का सभा में गोलमाल किया गया है।

धर्मशाला में शुरु हुआ जीआईएस सर्वे

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नगर निगम धर्मशाला में अब जीआईएस मैपिंग के आधार पर लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए शहर के सभी 17 वार्डों में जीआईएस (ग्लोबल इंफार्मेशन सिस्टम) से सर्वेक्षण करने का काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे के बाद लोगों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स चुकाना पड़ेगा। एमसी ने सर्वे का जिम्मा निजी कंपनी का सौंपा है, जो सर्वे के बाद शहर के सभी भवनों की वास्तविक संख्या का ब्योरा नगर निगम को देगी।

धर्मशाला को तीन साल पहले नगर परिषद को भंग कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नगर परिषद में शहर के साथ लगती खनियारा, सिद्धपुर, सिद्धबाड़ी, गबली दाड़ी, ऊपरली दाड़ी, बड़ोल, सकोह, मंत और कजलोट पंचायत का कुछ हिस्सा शामिल कर नगर निगम बनाई गई है। अभी तक मर्ज एरिया से कोई प्रहपटी टैक्स नहीं वसूला जाता है।

फिलहाल पुराने नियमों के आधार नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स पुराने एरिया में वसूल रही है। अब मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक जीआईएस आधारित सर्वे हो रहा है। उसके बाद निगम नई दरों के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स तय करेगा। सर्वे को पूरा करने के बाद इसे नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके तहत भवन मालिक, भवन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, मालिक का नाम, फोन नंबर, भवन का क्षेत्रफल घर बैठे जान जा सकेगा।

नगर निगम एरिया की हर प्रॉपर्टी की एक यूनीक आईडी बनेगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक से पूरी आईडी का बायोडाटा निकल आएगा। इसके माध्यम से ही प्रत्येक मकान का नक्शा तैयार होता है। साथ ही सर्वे एजेंसी मकान को एक यूनीक नंबर देती है, जिसमें मकान का क्षेत्रफल, ऊंचाई-लंबाई, सदस्यों की संख्या, कारोबार से लेकर पूरी लोकेशन का ब्योरा दर्ज करेगी। इसके आधार पर ही हर मकान का हाउस टैक्स तय होगा।

चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए जिला में सहायक व्यय प्रेक्षक तैनात: उपायुक्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि लोकसभा सामान्य चुनाव 2019 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करवाने के लिए तथा चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए जिला में सहायक व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सहायक प्रबंधक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बिलासपुर आरएस सरमान मोबाइल नंबर-8219243162 को विधानसभा क्षेत्र 46 झंडूता, रणवीर कुमार पांडे मोबाइल नंबर 70181-96539 केनरा बैंक बिलासपुर को 47 घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र, अचल ठाकुर मोबाइल नंबर 70183-20976 पंजाब नेशनल बैंक बरमाणा को विधानसभा क्षेत्र 48 बिलासपुर तथा प्रकाश धर्माणी मोबाइल नंबर 94187-71183 सहायक प्रबंधक ओरियंटल बैंक ऑफ कहमर्स को विधानसभा क्षेत्र 49 श्रीनयना देवी जी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निखिल बजाज मोबाइल नंबर 98882-33133 बैंक ऑफ इंडिया और चंदन शर्मा मोबाइल नंबर 94184-71655 पंजाब नेशनल बैंक दयोथ को रिजर्व रखा गया है।

नैक की टीम ने किया नौरा कॉलेज का निरीक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

राजकीय महाविद्यालय नौरा में कुछ दिन पूर्व ही नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल) की टीम ने दौरा किया। टीम ने दो दिन विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसमें पाठ्यक्रम, शोध, नेतृत्व एवं संगठन, अभिभावक संगठन, पूर्व छात्र संगठन और स्टाफ सहित अन्य जानकारियां हासिल की।

वहीं टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों, स्टाफ सदस्यों और पूर्व छात्र संघ के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा कॉलेज में खेलकूद, सांस्कृतिक संसाधनों, पुस्तकालय और प्रलेखन का भी निरीक्षण किया। विद्यार्थियों ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं। टीम में नीलांबर विश्वविद्यालय झारखंड के प्रो. एसआई, पुणे विश्वविद्यालय के प्रो. प्रकाश पाटिल और प्रो. पवन पौडर शामिल रहे। टीम निरीक्षण की रिपोर्ट नैक को देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही महाविद्यालय को नैक का ग्रेड मिलेगा। इस मौके पर प्रो. कमल, प्रो. पवन, प्रो. एलआर नेगी, प्रो. नेमराज, प्रो. राजीव, प्रो. अरुण, प्रो. संजीव और प्रो. विपिन आदि मौजूद रहे।

सफेद हाथी बनी सिंचाई योजना, किसानों को नहीं मिला लाभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

सवा सौ करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई उठाऊ सिंचाई योजना सुन्हाणी आज सफेद हाथी साबित हो रही है। करीब चार साल पहले इस योजना का उद्घाटन हो चुका है लेकिन इसका लगभग चार वर्ष बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक पानी के स्टोरेज टैंक के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

सुन्हाणी गांव के किसान सुरेंद्र कौशल ने बताया कि इस योजना के न चलने के कारण उनकी उपजाऊ भूमि बरसात के पानी पर ही टिकी हुई है यदि बरसात न हो या ज्यादा हो तो उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं।

किसान दिनेश कुमार कौशल ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए उनको सिंचाई का पानी चाहिए था, ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी उन्हें योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि योजना का आनन-फानन में बिना मशीनरी लगे उद्घाटन भी कर दिया गया था। उद्घाटन के तीन वर्ष बाद विभाग ने मशीनें तो लगा दी हैं लेकिन खेतों तक अभी पानी नहीं पहुंच पाया है जिससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

गांव लेहड़ के सुरेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले किसान खेतों में सिंचाई न होने की समस्या झेलने को मजबूर हैं। लाखों रुपये लगाकर सूखे की मार से निपटने के लिए सिंचाई योजना बनाई गई थी, लेकिन विभाग योजना को चालू न करके उनके साथ अन्याय कर रहा है। विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही योजना को शुरू नहीं किया गया तो मजबूरन लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

गर्मियां आते ही पीलिया की चपेट में आने लगे लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही डायरिया के साथ-साथ लोग पीलिया रोग की चपेट में आने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बीते सप्ताह कुल तीन मामले पीलिया के पॉजीटिव निकले हैं। वहीं वर्तमान में डायरिया के भी करीब एक से डेढ़ दर्जन मरीज अस्पताल में उपचार को पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बीते सप्ताह उपचार को आए दो पुरुषों और एक महिला की जब चिकित्सकों ने जांच की तो यह तीनों पीलिया से पीड़ित पाए गए।

पीलिया से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा व आंखें पीली पड़ना शुरू हो जाती है, वहीं व्यक्ति का मूत्र भी अत्यधिक पीला हो जाता है। इसके साथ-साथ पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी, सिरदर्द, जी मिचलाना, भूख न लगना आदि लक्षण पाए जाते हैं। चिकित्सकों ने लक्षण दिखने पर झाड़ फूंक करवाने की बजाय सीधा डाक्टरों को दिखाने का आग्रह किया है।

लक्षण: त्वचा व आंखें पीली पड़ना, मूत्र पीला होना, कमजोरी, सिरदर्द, जी मिचलाना, भूख न लगना आदि।

पीलिया से बचाव: बाहर का खाना न खाएं, ताजा और उबला हुआ खाने को प्राथमिकता दें, लक्षण दिखने पर चिकित्सक को दिखाएं, झाड़ फूंक से बचें, सीधा डाक्टर को दिखाएं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचली संगीत की बेहतरीन अदाकारा की हादसे में मौत

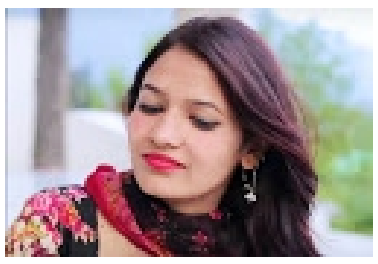

द रीव टाइम्स ब्यूरो

'ओ बांकी चंद्रा याद रखी गल्लां मेरी' ओ गीत में नाटी किंग ठाकुर दास राठी के साथ बांकी चंद्रा का किरदार निभाने वाली शांघड़ की रजनी ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। हुरला के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में घायल शांघड़ की रजनी (21) पुत्री शेर सिंह की मौत हो गई है।

घायल रजनी को डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर किया था, लेकिन पीजीआई ले जाते उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। बांकी चंद्रा के नाम से जानी जाने वाली रजनी गड़सा में जेबीटी कर रही थीं। उन्होंने ठाकुर दास राठी के गीत ..हवा लागी चंडीगढ़ा री में बतौर कोआर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद ओ बांकी चंद्रा गीत में ठाकुर दास राठी के साथ

लगातार हादसों के बाद पर्यटन विभाग ने 44 पैराग्लाइडर पर कसा शिकंजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पैराग्लाइडिंग के दौरान हो रहे हादसों को रोकने के लिए पैराग्लाइडिंग तकनीकी जांच समिति सख्त हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक की अगुवाई में जिले की कई पैराग्लाडिंग साइटों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 44 पैराग्लाइडरों में निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गईं। कार्रवाई करते हुए टीम ने 44 पैराग्लाइडरों की उड़ान पर रोक लगा दी है।

ये पर्यटन सीजन में उड़ान नहीं भर सकेंगे। टीम की इस कार्रवाई से पैराग्लाइडिंग साइट डोभी, सोलंगनाला और तलोगी में जांच को पहुंची टीम से साहसिक गतिविधियों का संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया है। समिति के अध्यक्ष और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा के साथ जिला पर्यटन अधिकारी बीसी नेगी ने तीन दिन निरीक्षण किया। पहले दिन जिला मुख्यालय के साथ लगते डोभी पैराग्लाडर साइट में आधुनिक पोरोसिटी मशीन से पैराग्लाइडरों की टेस्टिंग की।

डोभी में 150 पैराग्लाडर में से छह की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोलंगनाला में 198 पैराग्लाइडर की जांच की गई। यहां 38 पैराग्लाइडर में खामियां पाई गई और इनकी उड़ान पर भी रोक लगा दी गई है। जिला पर्यटन अधिकारी बीसी नेगी ने कहा कि 44 पैराग्लाइडरों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है।

खुले में कूड़ा फेंकने पर होगा एक लाख का जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो , कुल्लू

जिला में खुले में कूड़ा-कचरे फेंकने की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला के शहर, उपनगर और पर्यटन स्थलों पर कूड़ा फैलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण को दूषित करने वाले व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की ढील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर प्लास्टिक कचरे की समस्या हो रही है। उपायुक्त कुल्लू ने राष्ट्रीय राजमार्गों, ब्यास नदी तथा इसकी अन्य सहायक नदी-नालों, शहरों व गांवों में जहां कहीं पर भी कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकते पाया जाता है तो मौके पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। यूनुस ने कहा कि जिला के शहरी इलाकों के साथ पर्यटन स्थलों व नदियों के किनारे कूड़ा फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थलों की निगरानी की जा रही है और इसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। जिला में कचरे को लेकर एनजीटी भी सख्त है और जून माह में राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट दी जाएगी।

सी फार्म जमा न करवाने पर 2409 युवाओं के बेरोजगारी भत्ते पर रोक

द रीव टाइम्स, चंबा

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे युवाओं को सी फार्म जमा करवाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक जब तक बेरोजगार युवा सी फार्म जमा नहीं करवाते हैं, तब तक उनके बेरोजगारी भत्ते पर रोक रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई से युवाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं, बेरोजगार भत्ता मिलने की आस लगाए बैठे युवाओं को उनकी भूल भारी पड़ती ही दिख रही है।

विभागीय जानकारी के अनुसार जिला के 2609 बेरोजगार युवा सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे है। हर माह विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ते की किस्त का भुगतान किया जाता है। लेकिन अप्रैल माह के शुरू होने के बाद बेरोजगार युवाओं को सी फार्म जमा करवाना अनिवार्य है। हालांकि अभी तक करीब दो सौ युवाओं ने यह फार्म जमा करवा दी है। जबकि शेष 2409 बेरोजगारों को सी फार्म जमा न करवाने के चलते बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। सी फार्म जमा करवाने के बाद बेरोजगारों को बैकलॉग भत्ते की किस्त का भुगतान किया जाएगा। सी फार्म युवा ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे भरकर विभाग के पास जमा करवाना होगा।

क्या है सी फार्म

हर साल बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जारी रखने के लिए सी फार्म जमा करवाना होता है। इसके तहत बेरोजगार अभ्यर्थी यह घोषणा करता है कि उसे अभी तक किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है और वह इस योजना से लाभान्वित होने के लिए पात्र है। वहीं, कौशल विकास भत्ता योजना के तहत भी प्रशिक्षण की जानकारी देनी होती है।

सप्रेम अभियान में 15179 नए मतदाताओं का पंजीकरण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

जिला प्रशासन का मतदाता जागरूकता को समर्पित सप्रेम अभियान रंग लाने लगा है। मतदाता पंजीकरण टीमें महज दो हफ्ते में जिलेभर में 15,179 नए लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने में सफल रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि अभियान के पहले चरण में 26 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रशासन की टीमों ने घर-घर जाकर हर मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क साधा और पात्र लोगों का पंजीकरण किया। साथ ही सभी मतदाताओं को 19 मई को मताधिकार के प्रयोग को लेकर प्रोत्साहित किया।

इस दौरान सवा तीन लाख से अधिक लोगों को मतदान को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने 19 मार्च को मंडी के सेरी मंच से स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिए सप्रेम यानी संपर्क प्रत्येक मतदाता अभियान की शुरुआत की थी।

उपायुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान पंजीकरण और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ ही दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं की मतदान को लेकर जरूरतों का भी पता लगाया।

पेन को मुंह से पकड़कर दी परीक्षा और 89 फीसदी अंक पाए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रजत के हाथ नहीं रहे तो उसने मुंह से कलम पकड़ने और उससे लिखने का अभ्यास शुरू किया। उसने पढ़ाई जारी रखी और बीते दिन प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 404 अंक (88.80 प्रतिशत) हासिल किए।

उसने सभी पेपर बिना किसी राइटर के दिए। न ही बोर्ड से कभी अतिरिक्त समय मांगा। रजत को मुंह और दांतों में कलम फंसाकर लिखता देख हर कोई दांतों तले अंगुलियां दबा लेता है। हिमालयन महडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी के छात्र रजत के 2009 में बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए।

इतना ही नहीं होनहार छात्र बिन हाथों के ऐसी चित्रकारी करता है कि एक बेहतर चित्रकार भी दंग रह जाए। स्कूल में हमेशा अव्वल आता है। रजत एक बेहतरीन फुटबाल खिलाड़ी भी है। स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र ठाकुर रजत की उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उनके अनुसार रजत अन्य सभी लड़कों से अलग है। उसका जोश और जुनून सभी छात्रों को एक प्रेरणा देता है।

रजेरा पंचायत के तीन गांवों में चार माह से बिजली नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

रजेरा पंचायत के तीन गांवों में चार माह से बिजली की आपूर्ति ठप है। इस कारण एक दर्जन परिवार अंधेरे में रातें गुजारने को मजबूर हैं। इसका मुख्य कारण बोर्ड की लापरवाही है। क्योंकि बिजली बोर्ड ने गांव को जाने वाली बिजली लाइन को चार माह से दुरुस्त ही नहीं करवाया है। हालांकि ग्रामीण बिजली बहाल करवाने को लेकर बोर्ड के अधिकारी से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को हर बार आश्वासन ही हाथ लगा है। रजेरा पंचायत के हडार, कुटा, द्रबड़ गांव में चार माह से बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है।

प्रभावित परिवारों में धर्म सिंह, रत्न चंद, बजर सिंह, हेम राज और मोटा राम ने बताया कि चार माह पहले भारी बारिश के कारण बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी, जो कि आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई। गांव में जगह-जगह बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हैं। ग्रामीण बोर्ड को इतना भी बोल चुके हैं कि बिजली लाइन दुरुस्त करवाने में वे बोर्ड का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना बोलने के बाद भी बोर्ड गांव में बिजली सप्लाई बहाल नहीं कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है।

जान जोखिम में डालकर कीनाला-कुठेड़ मार्ग से गुजर रहे छोटे वाहन

द रीव टाइम्स, चंबा

जनजातीय क्षेत्र होली के कीनाला-कुठेड़ संपर्क मार्ग पर वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे है। यह मार्ग छोटे वाहनों के लिए भले ही खुल गया है, लेकिन अभी तक यहां सड़क किनारे मलबे के ढेर लगे हैं। इस कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने मार्ग बहाल करने के लिए मलबा सड़क किनारे ही फेंका दिया है। इस कारण यहां कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द उक्त मार्ग पर सड़क किनारे एकत्रित मलबे को हटाया जाए।

इस बार सर्दियों में भारी हिमपात हुआ है। इसके चतले संपर्क मार्गों को काफी नुकसान हुआ है। होली क्षेत्र के इस मार्ग पर भी भूस्खलन हुआ था। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी है, लेकिन अभी भी सड़क किनारे फेंका मलबा नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों में विनोद कुमार, अजय कुमार, दलीप सिंह, राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, दीपक सिंह, रणवीर सिंह, पूर्ण चंद ने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए। ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

कूंर स्कूल में शिक्षकों की कमी से 40 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

रावमापा कूंर में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल से विद्यार्थी अन्य स्कूलों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कूंर के उपप्रधान सुदेश कुमार ने उपायुक्त चंबा हरिकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने प्रशासन को बताया कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि इसी साल करीब चालीस विद्यार्थियों ने छतराड़ी स्कूल का रुख कर लिया है। स्टाफ की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने भले ही स्कूल खोल दिया। मगर स्टाफ की व्यवस्था करना सरकार भूल गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द उक्त स्कूल में स्टाफ की तैनाती की जाए। इससे छात्र-छात्राओं को परेशानियां न पेश आए।

दर्दनाक हादसे की तस्वीरें: इधर-उधर बिखरीं लाशें 6 की मौत, हर तरफ चीख-पुकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

हिमाचल प्रदेश मंडी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पधर उपमंडल के अंतर्गत पधर-बल्ह- टिक्कर मार्ग पर फागनी (ठंडा मगरू) के पास हुआ है। सभी गाड़ी में सवार होकर आधार कार्ड अपडेट करवाने चौंतड़ा जा रहे थे कि रास्ते में हादसा हो गया । मैक्स कैब जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

दो दशकों से नहीं बन सका बंजार का बाईपास रोड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू के बंजार में बाईपास सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। करीब दो दशकों से बंजार के बाईपास का निर्माण कार्य लटका है। इसका खामियाजा न केवल बंजार शहर की जनता, बल्कि सैलानियों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा जोरशोर से गरमाने लगा है।

पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान मंत्री ने भी बाईपास निर्माण की घोषणा की थी। लोकसभा चुनावों में जनता भी अब राजनीतिक दलों से जवाब मांग रही है। शहर के बीचोंबीच बंजार के सिधवां से लेकर शेगलू बाजार तक गुजरने वाला हाईवे-305 इतना संकरा है कि यहां एक बार बस फंस जाए तो उसे निकालने में एक घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। स्थानीय निवासी संजीव ठाकुर, नरेश शर्मा, उपेंद्र, सतपाल, प्रताप, ऐले राम, राम कृष्ण, हंस राज, मिताली, धर्मेंद्र, शिव राज, भूपाल, ललित, मोहर सिंह, राजू, प्रदीप सिंह का कहना है कि बंजार में दो दशकों से बाईपास सड़क निर्माण की मांग चल रही है।

चुनावी ड्यूटी में गए शिक्षक 47 स्कूलों में पढ़ाई हुई ठप

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से सराज और करसोग के 47 प्राइमरी स्कूल खाली हो गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सराज शिक्षा खंड में 33 प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। करसोग शिक्षा खंड के भी 14 स्कूलों के अध्यापक चुनाव ड्यूटी पर हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इन स्कूलों के अध्यापकों के चुनावी ड्यूटी पर चले जाने के बाद इन स्कूलों की एसएमसी को आदेश दिए गए हैं कि वह इस दौरान स्कूलों की जिम्मेदारी संभालें और बच्चों की देखभाल भी करें। एक तो इन दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी कभी पूरी नहीं होती और ऐसे में एक साथ इतने स्कूलों के सभी अध्यापकों की ड्यूटी लगाने से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।

महिलाएं शादी करने से पहले अपने अधिकारों को जानें

- कई बार ऐसा होता है, कि औरत खुद में ही अपनी परेशानी झेलती रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती इस डर से कि कुछ हो नहीं सकता, कोई कर भी क्या लेगा, लेकिन ठहरिये आप शायद ये भूल रही हैं कि आपको ऐसे कई अधिकार प्राप्त हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है ।
- मार्च 1972 में, एक आदिवासी लड़की का पुलिस थाने में ही पुलिसकर्मियों ने बलात्कार कर दिया था। इस मामले में शोर इसलिए मचा था, क्योंकि जिन पर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही उसके साथ गलत किया। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक साल 2005 से 2010 के बीच पुलिस थानों में बलात्कार के लगभग 40 मामले सामने आये थे, जबकि ये भी सच है कि जितने मामले सामने आते हैं उससे कहीं अधिक घटित हुये होते हैं।
- यदि हम सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों पर जायें तो किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सही शब्दों में कहें तो शाम 5:30 के बाद थाने में नहीं रखा जा सकता और तो और पूछताछ के दौरान महिला के साथ किसी महिला अफसर की उपस्थिति भी अनिवार्य है, लेकिन देखा जाता है महिलाओं को फिर भी परेशान किया जाता है और इस तरह के मामलों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कानूनी अधिकारों की सही जानकारी का न होना

औरत कर सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR

- छेड़छाड़, बलात्कार या किसी भी तरह के उत्पीड़न संबंधी फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट (FIR) किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही अपराध संबंधित थाना क्षेत्र में हुआ हो या न हुआ हो। वह थाना उस रिपोर्ट को संबंधित थाने को ट्रांसफर कर सकता है। केंद्र सरकार ने निर्भया मामले के बाद सभी राज्यों को अपराध होते ही जीरो एफआईआर करने को कह दिया था और पुलिस यदि किसी महिला की शिकायत दर्ज करने से मना कर दे तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

औरत को प्राप्त है उसकी निजता का अधिकार

- किसी भी मामले में नाम आने पर पुलिस या मीडिया किसी के भी पास ये अधिकार नहीं है, कि वे संबंधित महिला का नाम उजागर करें । पीड़िता का नाम उजागर करना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा पीड़िता को सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए किया जाता है। बलात्कार की शिकार महिला अपना बयान सीधे-सीधे जिला मजिस्ट्रेट को दर्ज करा सकती है, जहां किसी और की उपस्थिति जरूरी नहीं है।

FIR दर्ज कराने से पहले औरत अपने लिए मांग सकती है डॉक्टरी सहायता

पहले बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद होती थी, लेकिन अब फॉरेंसिक मेडिकल केयर फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बलात्कार पीड़िता FIR दर्ज कराये बगैर भी डॉक्टरी परीक्षण के लिए डॉक्टर मांग सकती है। कुछ मामलों में तो पुलिसकर्मी ही पीड़िता को जांच कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता था। अब मेडिकल मुआयना करवाने से पहले पीड़िता को डॉक्टर को सारी प्रक्रिया समझानी होती है और उसकी लिखित सहमति लेनी होती है। पीड़िता यदि चाहे तो मेडिकल टेस्ट देने से मना भी कर सकती है।

मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार

जिस महिला का बलात्कार हुआ है, वो कानूनी मदद के लिए मुफ्त मदद मांग सकती है और ये जिम्मेदारी स्टेशन हाउस अधिकारी की होती है, कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए जल्द से जल्द सूचित करे।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याएं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

यूरिक एसिड हो सकता है ख़तरनाक

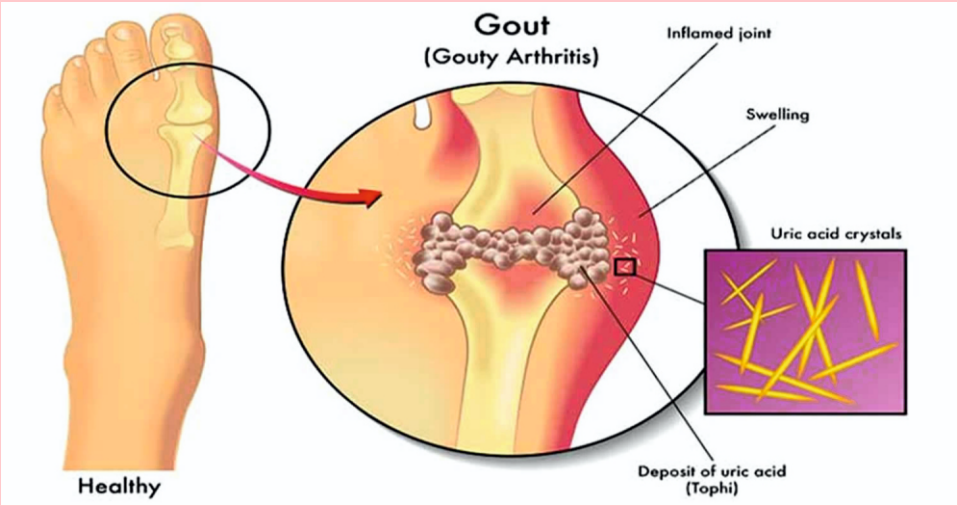

- शरीर में पाए जाने वाले हर एक तत्व की मात्रा जब तक संतुलित बनी रहती है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है लेकिन जब किसी भी तत्व की मात्रा थोड़ी सी भी कम-ज़्यादा होने लगती है तो इसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगता है जैसे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से गाउट रोग हो जाता है जो एक प्रकार का गठिया रोग ही होता है जिसमें शरीर के जोड़ों में बहुत दर्द रहने लगता है।
- यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बना कम्पाउंड होता है जो शरीर को प्रोटीन से एमिनो अम्लों के रूप में प्राप्त होता है। इस एसिड की सामान्य मात्रा तो यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है लेकिन जब इसकी ज्यादा मात्रा शरीर में बनने लगती है तो ये मात्रा बाहर निकलने की बजाये शरीर में ही जमा होती जाती है और गठिया का रूप ले लेती है।
- एमिनो एसिड्स के संयोजन से प्रोटीन बना होता है और जब पाचन के दौरान प्रोटीन टूटता है तो इस प्रक्रिया में प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है।
- अगर 25 साल की उम्र के बाद कम शारीरिक श्रम करते हुए प्रोटीन की ज्यादा मात्रा का सेवन किया जाता है तो यही प्रोटीन शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाने लगता है। इस एसिड की बढ़ी हुयी मात्रा छोटे-छोटे क्रिस्टल्स के रूप में हड्डियों के जोड़ों के आसपास जमा होने लगती है। ये क्रिस्टल्स बहुत नुकीले होते हैं जो जोड़ों की चिकनी झिल्ली में चुभते हैं जिससे भयंकर दर्द होता है। रात में ये दर्द बढ़ जाता है और सुबह शरीर में अकड़न महसूस होती है।

यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण

- कुछ लोगों में यूरिक एसिड का बढ़ना वंशानुगत होता है यानी उनकी हर पीढ़ी में इस एसिड के बढ़ने की समस्या पायी जाती है।
- किडनी द्वारा सीरम यूरिक एसिड का कम उत्सर्जन करने से भी इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है।
- तेजी से वजन घटाने या उपवास की प्रक्रिया में भी इस एसिड का स्तर काफी तेजी से बढ़ जाता है।
- डायबिटीज की दवाएं और पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं भी इस एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं।

यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाले नुकसान

- शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से शरीर के छोटे जोड़ों में दर्द रहने लगता है जिसे गाउट रोग कहते हैं।
- अगर किडनी की भीतरी दीवारों की लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे किडनी में स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है।
- इसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर कार्डियोवैस्कुलर रोग और मेटाबोलिक सिन्ड्रोम का कारण भी बन सकता है।
- यूरिक एसिड की मात्रा के बढ़ने से शरीर को होने वाली तकलीफ का अंदाजा अब हो ही गया होगा । ऐसे में इस एसिड की मात्रा को बढ़ने से रोकने के लिए संतुलित आहार का लिया जाना बेहद जरूरी है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स का संतुलन हो ताकि किसी भी एक तत्व की मात्रा ना कम हो सके और ना ही अधिक ।

इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर भी यूरिक एसिड की बढ़ी हुयी मात्रा से बचाव सम्भव है क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा पीने से शरीर में मौजूद यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा यूरिन के जरिये बाहर निकाली जा सकती है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

पब्लिक और निजी शौचालय का इस्तेमाल करते समय ये भी ध्यान दें

सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना पसंद तो कम ही लोग करते हैं लेकिन मज़बूरी में करना ही पड़ जाता है। कोई पब्लिक टॉयलेट भले ही कितना भी साफ क्यों न दिखे, लेकिन उसमें बहुत अधिक मात्रा में कीटाणु होते हैं। इसका कारण ये है कि पब्लिक टॉयलेट को बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं । इसलिए आपको द रीव टाइम्स बता रहा है कि किन सावधानियों का ध्यान रखें जब आप शौचालयों का उपयोग करें :

टिशू पेपर से दरवाजा खोलना

वाशरूम में जाने के लिए सबसे पहले आपको दरवाजा खोलना पड़ता है। दरवाजा खोलने के लिए आप उस पर लगे हैंडल को पकड़ते हैं और यही वो जगह है जहां से आप कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। ये कीटाणु आपको कई गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। इसलिए इनसे सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए, टिशू पेपर से दरवाजे का हैंडल पकड़ें। हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

टॉयलेट सीट को टॉयलेट पेपर से साफ करना

टॉयलेट में जाते ही टॉयलेट सीट को देखें, और अगर ज़रूरी लगे तो टॉयलेट पेपर से सीट कवर साफ करें। आप फार्मेसी स्टोर में मिलने वाले सीट कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये छोटे से पैक में मिलते हैं और आपकी जेब या बैग में आसानी से आ जाते हैं।

हाथ से न दबाएं फ्लश बटन

टॉयलेट का इस्तेमाल करके सभी फ्लश बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फ्लश बटन पर कीटाणु होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लश दबाने के लिए टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें और फिर उसे फ्लश में ही डाल दें।

फ्लश के फौरन बाद बाहर निकलें

फ्लश की स्पीड बहुत तेज होने से आप तक कई कीटाणुं पहुंच सकते हैं। ये कीटाणुं आपकी श्वास नली में पहुंच सकते हैं और गले का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जब आप फ्लश करें, तो फौरन टॉयलेट से बाहर आ जाएं। दूसरा विकल्प ये है कि टॉयलेट की सीट को बंद कर दें।

अच्छी तरह से हाथ धोएं

अगला स्टेप हाथ धोने का होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तिहाई बीमारियां ठीक से हाथ न धोने की वजह से होती हैं। हाथ धोने के लिए लिक्विड हैंड वॉश ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि साबुन से कीटाणु फैलने का अधिक जोखिम होता है।

टिशू पेपर से हाथ साफ करें

इन दिनों भले ही हैंड ड्रायर पापुलर हो गए हैं लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि टिशू पेपर से हाथ साफ करना ज्यादा प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हैंड ड्रायर आपके हाथ ठीक से साफ नहीं करते बल्कि उससे आने वाली गर्म हवा से बैक्टीरिया जल्दी फैलता है।

और आखिर में हैंड सेनेटाइजर

याद रखें कि पब्लिक टॉयलेट का मेन डोर भी बहुत सारे इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए हाथ धोकर सुखाने के बाद भी आपका एक्स्ट्रा प्राटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप बाहर निकलने के बाद हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें। आप मेन डोर खोलने के लिए भी टिशू का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये सारी बातें यदि हम घर और कार्यालय में भी उपयोग में लाएँ तो सभ्य तरीक़े से स्वस्थता को अपनाया जा सकता है ।

INDIA FACES LEADERSHIP CRISES

India is evolving as a country where every fifth person intends to emerge as so called leader because politics is seen as a good career opportunity by majority of those who either fail to choose different career or lack confidence to adopt a successful career. On the other hand, the talented youths who sincerely wish to work for development are losing interest in politics as they are afraid of its ugly face. Ultimately, 135 crore population is bound to bear with the existing scenario of leadership.

It is here important to define 'who is a leader.' Can all those people who are getting elected and occupying seats in legislation enjoying pension benefits throughout their life irrespective of consecutively been elected, be termed as leaders? Perhaps Not! They are enjoying public facilities with temporary VIP status with discretionary powers to distribute a defined quantum of money in their constituencies which majority of them usually fail to do so.

In fact, leader is one who has clear and unbiased vision to transform the nation by taking all corrective and productive measures so as to create an ample space for harmony, economic growth and evolution for everyone, especially the new generation.

Unfortunately, our history reveals otherwise where our leadership dealt the country with utmost biasness, favouritism and with short sightedness.

We could have saved Bhagat Singh, Raj Guru and Sukh Dev from being hanged had Mohan Dass Karam Chand Gandhi intervened during judicial proceedings. Country could have seen Netaji Subhash Chandra Bose as the first Prime Minister of India had Gandhi controlled his ego and his obsession with Jawahar Lal Nehru.

Lakhs of lives in Kashmir could have been saved, had Jawahar Lal Nehru agreed to the advice of Dr. Rajendra Prasad to avoid the backdoor entry of Article 35A in the constitution. Kashmir could have been saved from languishing, had Jawahar Lal Nehru shown real patriotism while agreeing to the terms of his 'so called' cousin Sheikh Abdullah to add another constitutionally discriminating Article 370. India could have gained position in Security Council long back had Nehru not passed the opportunity to China.

There are numerous such political decisions which have cast a dark shadow on the future of our country. But today, who is bothered about such blunders of the past? Does anyone in the present scenario have guts to touch upon all these aspects and propagate corrective measures to safeguard the country? It seems like every one in politics is absorbed in JOD-TOD to win elections.

The Congress party does not have any agenda on correcting the past mistakes, rather it keeps on promoting to keep the issues alive even today. They seemed to have learnt enough from the Britishers to keep the problems alive and joyfully rule the country on the analogy of "Divide and Rule". BJP was the party which came into existence in taking all such issues head-on, but has almost diluted its stance and is gradually becoming like Congress besides adding little to the past political blunders. There seems no exclusivity in BJP as has been propagated and the same has been witnessed from the complete silence of the party on its "Issues of Originality" during last five years of ruling the country. The Leftists' role has always been reversal right from beginning including distorting the history of the country. The regional parties have nothing to do with the country but they themselves want much more if support needed.

Then, who will think of the country and the pending cursing issues of the country? There was a revolutionary movement propagated by Anna Hazare wherein youth of the country seemed to be finally awakened and ready to bring change. But Aam Admi Party high jacked and killed this movement after coming into power in Delhi and people now feel deceived. There is hardly any scope of resurrection of similar movement in the country.

Then whom do we expect to take the corrective measures on all such historic blunders like Uniform Civil Code, Article 370, Article 35A, Ram Janm Bhoomi, Caste based Reservation, Illicit citizenship, and many more.

Now, God seems to be the sole saviour and we are ought to wait for the Kalki Awatar to take birth. Until then, let's be ready to loose even more.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

MADNESS WITHOUT METHOD

Those who travel in aeroplanes essentially can not frame policies or issue guidelines for those who reach their workplaces by transport buses. Education too is no exception when it comes to defining educational ethics. A teacher in gone by days used to be a guide and source of motivation and inspiration not only for his students but for society as a whole. Unnoticed, teachers fell victim to insouciance and undue interference of bureaucracy much before Indian independence during British rule. Legacy of Acharya Drone, Chanakya, Yagyavalkya, Guru Vishshth and Rishi Bhardwaj became subject to ignominy of administrators who themselves played stooges to politicians. Woods despatch and everything that followed was instrumental in tarnishing glorious service of teacher to an ordinary faculty. From Aashram system of imparting knowledge to no detention system and abrogating same within 8 years demonstrates nothing but challenged and dubious competence of policy makers. Education has been a laboratory over the years for insane experimentations. All these experiments added chaos to confusion. Most Government institutions today produce educated retards with exceptional anomalies. But fear of politicians suffocate every voice, if any, of protest that dare challenge and question their cerebral adroitness and intellectual prowess.

Teachers too are no less responsible for their own plight. Divided in thousands of unions all over the country they are controlled by strings well fastened with political fingers. The divide allowed teachers to compromise their reputiability and eminence. A teacher whose word once was taken for commandment throughout, lost all its authority. Decree of parents, *usko kya aata hey(?)* stuck to the psyche of his pupil so strenuously that every letter written on blackboard after that appeared blurred and stopped making any sense. The character more than information that once was fundamental qualification for teacher gradually got replaced by amount of intellectual garbage he stored in his brain. Intelligence and educational ethics henceforth were confused with intellectuality which started making of a society devoid of moral values. Education recently has become laboratory of experimentations, trials and mock-drills for bureaucracy more so for politicians ever since subject was transferred from state to concurrent list in mid seventies.

There are 25% private schools in India enrolling 40% of students in all. Poor quality education in govt schools make govt school teachers send their own children to private schools. Govt school teachers, surprisingly have no faith in government run schools and ASER report suggests that more than 95% govt school teachers in India depending upon the availability of private schools prefer private schools for the education of own children.

The problem essentially is not with government school teachers but with institutions run by government. Over the years an atmosphere in government run institutions has evolved where things like transfer and posting of the teacher in a school of his liking make him compromise his rectitude to a political stooge. And those few who gather courage to challenge a creeping social evil start appearing on political and public radar. A teacher and also a columnist in my acquaintance dared put a stop on immoral practices like copying during examination has been a target of public wrath. There can be thousand other examples where teachers suffered for their righteousness.

Hence, it is wrong to expect scrupulousness and high values or morality if a teacher is forced to be a target of incessant political grimace and public vilification or mud slinging. Teachers fail to decide which side they must take so that their teaching careers do not come to an abrupt end. How can teacher inculcate virtue and infuse students with high values if the teacher is persuaded by public to allow cheating during examination or threatened to bear the consequences? Therefore it is safe to say that we all have contributed our bit to bring down modern day education to this level. We as a society have converted teacher into a most confused creature. He hesitates to inculcate values like cheating is sinful or telling lies is bad in his students. The sin of telling lies got replaced by Nursery rhyme 'hahaha when asked by papa to open the mouth.'

With present day education system applying double standards we only are making a society of crippled minds, void of morals and values. Teachers are forced to take all responsibilities for this decline. Fear of being sent to some remote and far-off station often make him practise total reverse that which he actually holds on a very high esteem.

The present day education postulates a very grim scenario heading towards state of complete hopelessness. Day is not far when it reaches at a point of no return and govt school education system suffers a total collapse. This is the time politicians and bureaucrats start introspection and address real issues with education system. Success story of private schools without much of difference in infrastructure speaks volumes for itself. Big wads of notes with motifs of Mangalyan can not guarantee quality education in a govt school which is self evident when we compare it with private schools that never stops us wonder how at all can these budget schools perform so well with low paid teaching faculties. A teacher in budget school enjoys a far elevated status and exercises free will rendering his valuable services in making characters to build a better nation. No amount of money can replace dignity or respect of a teacher. Once a government school teacher regains his lost stature in the society everything will start reshaping. Until a teacher is given his due and unwarranted interference is stopped, teacher will fail to deliver which ultimately will result in crumbling down of whole system.

Kamlesh Sharma, Shimla (HP)
(Guest Writer) 9817540956

चमक-दमक की उड़ान में पंखों की थकान

कर्ज़ के बोझ में जेट एयरवेज़ की सांसे फूली

आजकल जेट एयरवेज की चर्चा हर जगह सुनने को मिल रही है । इसके पीछे कारण न केवल यह है कि इस सेवा को बंद कर दिया गया जिससे हज़ारों कर्मचारियों की रोजी-रोटी छिन गई है बल्कि दूसरा कारण यह भी है कि एक कैंसर से पीड़ित जेट एयरवेज के कर्मचारी ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जीवन इहलीला समाप्त कर दी। इसे इस एयरलाईंस के बंद होने से भी जोड़ा जा रहा है। जेट एयरवेज लगभग 26 बैंकों से 8 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़दार है जिसे चुकाना इसके बस से बाहर था। कर्ज़ पर कर्ज़ लेने के बाद सेवाओं की गुणवत्ता और बेलगाम खर्चों के कारण अंततः जेट एयरवेज़ के पंख थक गए और इस सेवा को विराम लग गया ।

जेट एयरवेज़ का घाटा बढ़कर 13 अरब रुपये के पार हो चुका था। इतना ही नहीं मार्च 2021 तक इसे 63 अरब रुपये कर्ज़ चुकाने हैं। जेट एयरवेज़ की ऐसी हालत पिछले लंबे समय से पटरी से बाहर ही चल रही थी। लगभग 11 वर्षों से इसकी माली हालत खस्ता होती गई। सेवाओं में भी गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। इतना ही नहीं कर्मचारियों की कई महीनों की तनख़्वाह भी उन्हें नहीं दी गई। इससे कर्मचारियों का भरोसा भी यह एयरलाईंस बरकरार नहीं रख पाई। साथ ही वित्तिय अनियमितताओं के चलते इसकी फज़ीहत इतनी हुई कि यह सरकार की नज़रों में भी अपनी साख खोता गया। वित्तिय गड़बड़ियों की शिकायत के बाद आयकर विभाग ने इस पर कई बार छापेमारी की ।

एयरवेज सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा इतनी है कि जेट एयरवेज खुद को इसमें बनाए रखने में असफल हो चुकी थी। इंडिगो से इसकी तुलना करते हैं तो पिछले दिनों जब इंडिगो ने प्रति सीट किराया कम किया तो जेट एयरवेज़ ने यथावत ही किराया रखा। इसका प्रभाव तो पड़ना ही था। नतीजन जेट को नुकसान उठाना पड़ा । 2017 की अगर बात करें तो ईंधन की कीमतों में भारी उछाल और बढ़ौतरी के कारण जेट एयरवेज को बड़ा घाटा उठाना पड़ा था ।

जेट एयरवेज की सेवाओं पर लोगों का विश्वास भी डांवाडोल होता रहा है । सुरक्षा में हो रही चूक हो या अन्य सेवाओं की बात...जेट की गंभीरता पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। कुछ समय पहले मुंबई से जयपुर जा रही जेट एयरवेज की फ्लाईट में अचानक लोगों की नाक

और कान से खून निकलने लगा। केबिन में वायु दाब बनाने वाले बटन को नहीं दबाने के कारण ऐसा हुआ। इसमें 31 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं 30 सितंबर को हैदराबाद से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने के बाद जेट एयरवेज की फ्लाईट 9W955 का इंजन फेल हो जाने के कारण इंदौर में इसकी आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसमें 100 से अधिक यात्रियों की जान का ख़तरे में आ गई थी। ऐसी लापरवाही विमानन क्षेत्र में विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल होती है। जेट के बाद यह बात कहना सही होगा कि भारत में हवाई यात्रा सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

सरकार का पक्ष इस विषय पर खामोशी साधे हुए है । यहां यह कहना ग़लत न होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरसंभव विमानन सेवा को बचाए रखने के संकेत दिए थे । उन्होंने स्वीकार किया था कि सरकार मद्द और सहायता करना चाहती है । उनके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था के संचालन और बेहतर जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन की प्रतिबद्धता दिखाई थी । किंतु सरकार भी लगता है कि इस झंझट से खुद को दूर ही रखने में भलाई समझ रही है। हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लग गया । सरकार ने वायदे किए थे जिस दिन हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, उसी दिन देश में समानता का बिगुल बजेगा। मोदी ने इसके लिए प्रयास भी किए । किंतु हवाई सेवाओं की दूर्दशा को देखते हुए ये वायदे खोखले ही नज़र आते हैं ।

अब यहां दीगर बात ये भी है कि इन विमानन कंपनियों ने बैंकों से हज़ारों करोड़ का कर्ज़ लेकर जो आतिशबाजियां छोड़ी है, उससे इनकी सेवाओं का अंत इसी प्रकार होना तय है। ये पैसा जो हज़ारों करोड़ का उनकी जेबों में जाता है और बाद में दिवालियापन घोषित कर चूना लगा लेते हैं, यह इस देश के आम लोगों की गाढ़ी कमाई का धन है । इस पर देश का विकास एवं तरक्की निहित है । जेट एयरवेज का कर्ज़ बढ़ता गया और इस पर किसी भी प्रकार की सीख लेने के बजाए एयरवेज ने इस कर्ज़े का बोझ और अधिक बढ़ाया और इसके अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को भी सुनिश्चित नहीं बना सकी । यही हाल कुछ अन्य हवाई सेवाओं के साथ भी हुआ । एयर सहारा, किंग फिशर, ईस्ट-वैस्ट एयरलाईन, स्काईलाईन आदि सभी बंद हो चुकी है । सरकार इस सभी विमानन सेवाओं के शेयर खरीदे और अपने स्वामित्व में ले लें....ऐसा संभव नहीं । निजी क्षेत्र में सेवाओं को पहले तो बर्बाद करो और फिर बर्बादी के बाद सरकार की ओर मुंह ताकते रहो और दिवालियापन की शिकार कंपनी को बचाने की गुहार लगाते रहो ।

जेट एयरवेज को आसमान से ज़मीन पर लाने के पीछे इस सेवा के चेयरमैन नरेश गोयल ने कोई कसर नहीं छोड़ी । कंपनी का दरबार वो या तो भारत में अपने घर पर ही लगाते थे या लंदन में घर पर । उन्होंने प्रबन्धन की कभी नहीं सुनी । साथ ही उनकी पत्नी की संचालन में ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण धीरे-धीरे जेट एयरवेज के 119 विमान अपने पंखों की परवाज़ ही भूल गए और अब मूक खड़ें हैं । दंपति की मनमानी के कारण हज़ारों कर्मचारी आज घर पर निठल्ले बैठे हैं ।

सरकार को इसके बावजूद भी उन कर्मचारियों के बारे में सोचने के लिए अग्रणी भूमिका में आना चाहिए जो अपना रोजगार छिनने के बाद सड़क पर आ गए हैं । उनका भविष्य उनके परिवार को भी अंधेरे में ले जाएगा । साथ ही बैंकों के हज़ारों करोड़ों की वसूली इन सरमायेदारों से किस प्रकार हो, इस पर भी सरकार को मंथन करने और गंभीर क़दम उठाने की दरकार है ।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की दरकार

हाल ही में दसवीं के परीक्षा परिणाम ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल निशान लगा दिया है। टॉपर्स की लिस्ट में प्रदेश के सैंकड़ों सरकारी स्कूलों में से केवल एक छात्रा मैट्रिक की मैरिट सूची में जगह बना पाई जबकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी छात्र पास नहीं हो पाया। यह पहला मौका नहीं है जब सरकारी स्कूलों की बोर्ड परिणामों में किरकिरी हुई है। ऐसा पहले भी होता आया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी स्कूलों के छात्र भरपूर मेहनत करने के बाद भी मैरिट सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते। इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा और स्कूलों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा पहले से चल रहे स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक पूरे हैं पर छात्र एक भी नहीं, तो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां छात्र तो हैं पर अध्यापक ही पूरे नहीं। जैसे तैसे खानापूर्ति के लिए सिलेबस पूरा किया जाता है और अंत में परीक्षा के दौरान छात्र अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। दो साल पूर्व जब दसवीं और बाहरवीं का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा था तो तत्कालीन सरकार ने शिक्षा प्रणाली की ओवरहॉलिंग करने के लिए अभियान चलाया। नतीजा करीब 40 ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया गया जिनमें पांच से कम छात्र थे। उन शिक्षकों को चार्जशीट करने की भी बात कहीं गई जिनके विषय में स्कूल विशेष में सभी छात्र फेल रहे। लगातार तीन साल के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के भी आदेश सरकार से निदेशालय को और निदेशालय से जिलों को जारी हुए। सरकार की इस कार्रवाई से शिक्षक जगत में हलचल मच गई। शिक्षकों का एक तबका ऐसा था जो खराब परिणाम का ठीकरा सीधा सरकार पर फोड़ रहा था। आज भी स्थिति इत्तर नहीं हैं। अधिकतर शिक्षकों का तर्क है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा कागजी कामों में उलझाया जाता है। अगर किसी स्कूल

में विषय विशेष से संबंधित अध्यापक ही नही तो उस स्कूल में कैसे बेहतर परिणाम की आशा की जा सकती है। यह तर्क कुछ हद तक सही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक या दो स्कूल ऐसे हैं जहां पर सरकार दावा करती है कि इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पढ़ाने के तौर तरीके निजी स्कूलों से कहीं बेहतर है। निःशुल्क वर्दी और निःशुल्क शिक्षा दो ऐसी योजनाएं हैं जिनके दम पर हर सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है और इसे ही अपनी सफलता मानतीं है। निःशुल्क शिक्षा समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने में बेहतरीन प्रयास है इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारना भी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आखिर परिणाम ही यह तय करता है कि कोई भी सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है।

बहरहाल जो परिणाम हाल ही में हमारे सामने है उसने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। हर कोई यह सोचने के मजबूर है कि कहीं निःशुल्क शिक्षा सुविधा के लालच में हम अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, क्या योजनाओं से केवल सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है, क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली बच्चों को उनके बेहतर भविष्य निर्माण में मदद कर पाएगी। ये वो यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब नीति नियंताओं को गंभीरता से ढूंढना होगा।

सनद रहे कि 29 अप्रैल को दसवीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मैरिट की सूची आई उसमें हमीरपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अर्थव ने 691 नंबर लेकर टॉप किया। इसके बाद अगले क्रम में टापर्स की फेहरिस्त में सरकारी स्कूलों से एक निधि के अलावा सभी निजी स्कलों के छात्रों के नाम दर्ज हैं। प्रदेश में इस बार कुल 1 लाख 11 हजार 980 छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें पास हुए 67319 छात्र । ये आंकड़ा परेशान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि इस बार का परीक्षा परीणाम बीते वर्ष के मुकाबले तीन फीसदी तक गिर गया। बीते वर्ष दसवीं का परीणाम 63.79 था जो इस वर्ष गिर कर 60.30 प्रतिशत तक आ गया।

अब एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। गाज एक बार फिर शिक्षकों के ऊपर गिराने की तैयारी है। लेकिन यह राग बहुत पुराना है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, इंक्रीमेंट रोकने की बात की जाती है और भी कई तरह के दावे किए जात हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता दिख नहीं रहा। अब बात एक बार फिर पुरानी शिक्षा पद्धति की ओर जाने की हो रही है। पहले की तर्ज पर पांचवी और आठवीं में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी । दसवीं के खराब परीक्षा परीणाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे को वजह माना जाना हास्यस्पद होने के साथ-साथ दुखद भी है। दरअसल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए जबकि अभी तक केवल प्रयोगात्मक कार्रवाई की जाती रही है। न तो प्रदेश में अध्यापकों के लिए कोई निश्चित ट्रांसफर पॉलिसी है और न ही शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोई ठोस व्यवस्था। ऐसे में सरकार शिक्षकों को और शिक्षक सरकारी व्यवस्थाओं को कोसते रहते हैं और स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था इसी नोंकझोंक में पिस कर रह जाती है।

शिक्षको का एक बड़ा तबका अपरोक्ष रूप से राजनीति करने में व्यस्त है, यह जगजाहिर है। शिक्षकों ने अलग अलग गुट बनाए है। सोशल मीडिया के जरिए एक जैसी विचारधारा वाले शिक्षकों को साथ जोड़कर अच्छा-खासा प्रभावशाली गुट तैयार किया जाता है और उसके बाद सरकार पर दबाव भी बनाया जाता है। शिक्षकों की इन गैर शिक्षण विधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने के साथ ही ऐसी शिक्षा नीति बनानी होगी जिससे स्कूलों की संख्या नहीं बल्कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो।

अंजना ठाकुर
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
anjna@iirdshimla.org

चुनावी हलचल लोकसभा चुनाव 2019

अंतिम चरण में 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल की चार सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। चारों सीटों पर दोनों ही दलों के प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। सभी नेताओं ने अपने अपने नामांकन के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही प्रत्याशियों के पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर भी प्रत्याशियों ने जानकारी दी। हिमाचल के सभी उम्मीद्वार करोड़ों की संपत्ति के मालिक है।

जानिए हिमाचल के किस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति

भाजपा

सुरेश कश्यप 85 लाख 80 हजार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप की चल अचल संपत्ति में पिछले डेढ़ साल में दोगुना इजाफा हुआ है। साल 2017 के हलफनामे के अनुसार उनके पास 14 लाख 10 हजार की चल संपत्ति थी जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार अब उनके पास 36 लाख 60 हजार की चल संपत्ति है। इसमें दो वाहन के अलावा सौ ग्राम सोन के आभूषण के और 50 हजार नकद शामिल है। इसी तरह 2017 में उनके पास 69 लाख 38 हजार की अचल संपत्ति थी जबकि वर्तमान में वह 85 लाख 80 हजार की संपत्ति के मालिक हैं।

भाजपा प्रत्याशी रामस्वरुप शर्मा की संपत्ति भी बढ़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पास साल 2014 में 2,05,555 कर चल संपत्ति थी। पांच साल बाद वर्ष 2019 में यह संपत्ति करीब 28,33,538 रुपये की हो गई है। चल संपत्ति में ही 26,27,983 रुपये बढ़ोतरी हुई है। अचल संपत्ति पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान 50 लाख थी, अब वह 62 लाख के करीब हो चुकी है। 12 लाख अचल संपत्ति बढ़ोतरी हुई है। जबकि उनकी पत्नी की चल व अचल संपत्ति में 17.17 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 में 19,73,316 रुपये की चल संपत्ति थी, अब 28,90,799 हो गई है। जबकि 2014 के लोस चुनाव में उनकी अचल संपत्ति 30 लाख थी। वर्तमान अचल संपत्ति 38 लाख हो गई है। अचल संपत्ति में आठ लाख जबकि चल संपत्ति में 9.17 लाख बढ़ोतरी हुई है।

कुल चल व अचल संपत्ति में 17.17 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

किशन कपूर की संपत्ति 5 करोड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांगड़ा-चंबा सीट से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में दिए नामांकन पत्र और 26 अप्रैल को लोक सभा के नामांकन पत्र के मुताबिक उनकी संपत्ति में लगभग 12 लाख की बढ़ोतरी हुई है। उनकी पत्नी की संपत्ति 18 लाख बढ़ी है। अचल संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 26 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में नामांकन पत्र दाखिल किया।

डेढ़ साल पहले कपूर की चल संपत्ति 91,61,340 रुपये थी। यह अब 1,04,63,282 रुपये हो गई है। उनकी पत्नी के पास चल संपत्ति 2017 में दी गई जानकारी के मुताबिक 28,45,600 रुपये थी। यह अब 46,58,549 रुपये हो गई है। दोनों के पास 265 ग्राम सोना है। बेटी के पास 3,83,108 रुपये और बेटे के पास 1,87,208 रुपये हैं। चारों के पास 47 हजार रुपये नकद राशि है। कपूर के पास होटल, घर और जमीन की कुल 5,85,50,000 रुपये और पत्नी के पास 68,00,000 रुपये की अचल संपत्ति है। किशन कपूर को लगभग 36 लाख की अन्य देनदारियां हैं।

करोड़ों के मालिक सांसद अनुराग ठाकुर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पिछले पांच साल के मुकाबले में अनुराग ठाकुर की संपत्ति 1 करोड़ 5 लाख रुपये बढ़ गई। अनुराग और उनकी पत्नी के नाम पर क्रमशः 3.25 लाख और 2.50 लाख रुपये कीमत के दो पिस्तौल हैं। इनमें से एक बेल्जियम निर्मित है। 26 अप्रैल को चुनाव आयोग को दिए शपथपत्र में अपनी संपत्ति 5.67 करोड़ दर्शाई है। अनुराग और उनकी पत्नी के पास 25 लाख 29 हजार की कीमत के 793 ग्राम सोने के आभूषण हैं। 1.25 लाख कीमत की एक सेंट्रो कार है, जो इसी साल 2019 में खरीदी गई है। पंजाब के कपूरथला, जालंधर, धर्मशाला, कुल्लू जिला और समीरपुर में लाखों की कीमत की भूमि एवं प्लॉट हैं। अनुराग और उनकी पत्नी के पास 25 लाख 29 हजार की कीमत के 793 ग्राम सोने के आभूषण हैं। 1.25 लाख कीमत की एक सेंट्रो कार है, जो इसी साल 2019 में खरीदी गई है।

कांग्रेस

डेढ़ साल में दोगुने धनी हो गए धनीराम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांग्रेस के टिकट पर शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी व वीरभद्र सरकार में पूर्व मंत्री डा. धनीराम शांडिल डेढ़ साल में लगभग दोगुना धनी हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने करीब 3.60 करोड़ की चल अचल संपत्ति घोषित की है जबकि डेढ़ साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने खुद करीब 1.07 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी।

संपत्ति की वर्तमान बाजार के दाम के बढ़ने के चलते पिछले हलफनामे के साथ तुलना में उनकी संपत्ति में दोगुना से ज्यादा के इजाफे की बात सामने आई है। शांडिल द्वारा शिमला में रिटर्निंग अफसर को सौंपे हलफनामे के अनुसार वह वर्तमान में करीब 1.60 करोड़ की चल संपत्ति के मालिक हैं। शांडिल ने 23 अप्रैल को शिमला संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया।

इसमें बैंक खातों में नकद जमा, खुद के पास नकदी के अलावा एक होंडा सिटी व एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं। इसके अलावा वह 2.07 करोड़ की अचल संपत्ति के भी मालिक हैं। वहीं, उनके ऊपर एक बैंक से 41 लाख 11 हजार रुपये का लोन भी है।

कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा की संपत्ति 3.41 करोड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मंडी से कांग्रेस के उम्मीद्वार आश्रय की उम्र 32 वर्ष है और उनके पास 97 लाख 69 हजार 270 रुपये की चल व 2 करोड़ 43 लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति है। कुल 3.41 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 43 लाख 94 हजार 395 रुपये की चल संपत्ति व 93 लाख 18 हजार रुपये का ऋण है। आश्रय पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। मंडी संसदीय सीट से आश्रय की उम्मीदवारी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आश्रय पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पिता अनिल शर्मा भाजपा में फिलहाल मंत्री है। हालात यह है कि आश्रय के पिता अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं कर रहे जबकि उनके दादा सुखराम अपने पोते के साथ खड़े हैं। ऐसे में परिवार में उलझी राजनीति पर सभी की नजर है।

डेढ़ साल में इतनी बढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल की संपत्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने 29 अप्रैल को धर्मशाला में नामांकन दाखिल किया। पवन काजल की ओर से निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक पिछले डेढ़ साल में विधायक पवन काजल की चल और अचल संपत्ति में लगभग 29 लाख रुपये का इजाफा हुआ है।

काजल की पत्नी के पास भी डेढ़ साल में 1,67,206 रुपये बढ़े हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में दिए नामांकन पत्र के ब्यौरे में काजल के पास कुल 1,48,90,757 रुपये की चल संपत्ति थी, जो बढ़कर 1,60,78,442 हो गई है। वहीं, 5,87,00,416 रुपये की अचल संपत्ति बढ़कर 6,04,20,993 रुपये की हो गई है। डेढ़ साल में काजल पर 66,42,582 रुपये की देनदारी बढ़ी है, जो पहले नहीं थी। इसके अलावा 42,12,363 रुपये का सरकारी लोन है। डेढ़ साल में काजल ने जेसीबी, जीप और एक ट्रैक्टर बेचा है, जिनकी वैल्यू लगभग 26 लाख रुपये थी। कांग्रेस प्रत्याशी पर कोई मामला दर्ज नहीं है।

डेढ़ साल में 19 लाख बढ़ गई रामलाल की संपत्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर की कुल संपत्ति डेढ़ साल में 19 लाख रुपये बढ़ गई। शपथपत्र में उन्होंने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति 3.48 करोड़ रुपये बताई है। चल संपत्ति 45.39 लाख और अचल संपत्ति 3.03 करोड़ है। इससे पूर्व 2017 के विधानसभा चुनावों के समय रामलाल ठाकुर ने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति 3.29 करोड़ रुपये बताई थी। जिसमें चल संपत्ति 32.15 लाख थी और अचल संपत्ति 2.97 करोड़ थी।

कोचिंग कैंप के लिए महिमा का हुआ चयन

रीव टाइम्स ब्यूरो

देवभूमि की एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर दस्तक देगी। हॉकी खिलाड़ी महिमा पुंडीर राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिताएं खेल चुकी हैं। फरवरी 2019 में हिसार में सीनियर नेशनल हॉकी स्पर्धा में बतौर गोलकीपर महिमा का शानदार प्रदर्शन रहा। इसके आधार पर उनका चयन सीनियर वुमन नेशनल कोचिंग कैंप साईं सेंटर बंगलूरू के लिए हुआ है। कैंप में चुनी जाने वाली महिमा प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी हैं। बंगलूरू में कैंप 26 अप्रैल से 9 जून तक चलेगा। हिसार में सीनियर नेशनल बी पूल के टूर्नामेंट 1 से 8 फरवरी तक हुए।

इसमें हिमाचल टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। बतौर गोलकीपर महिमा का प्रदर्शन शानदार रहा। गिरिपार के दुगाना गांव की महिमा ने कन्या हॉकी छात्रावास माजरा से खेल की बारीकियां सीखीं। माजरा से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की।

अब पांवटा कॉलेज में शिक्षारत हैं। माजरा हॉस्टल के कोच चंद्रशेखर ने महिमा की प्रतिभा को तराशा। इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में महिमा का प्रदर्शन शानदार रहा। इसके बाद हिसार में सीनियर नेशनल वुमन प्रतियोगिता से सब जूनियर और जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

सीएजी ने जांची विश्व प्रसिद्ध शिमला रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) राजीव महर्षि ने 25 अप्रैल को शिमला रेलवे स्टेशन का दौरा किया। शिमला से कालका रेल मार्ग से जाने के लिए सीएजी सुबह 10:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे।

इस मौके पर सीएजी ने शिमला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 और 2 का निरीक्षण किया। राजीव महर्षि ने कहा कि 'शिमला बेहद खूबसूरत शहर है और शिमला का हेरिटेज रेलवे स्टेशन यहां की शान है।

इस मौके पर रेलवे के एडीआरएम कर्ण सिंह, डीईएम शैलेंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक प्रिंस सेठी और वाणिज्य निरीक्षक अमर सिंह ठाकुर ने सीएजी को शिमला रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक के लिए लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी। सीएजी राजीव महर्षि 10:40 पर हिमालयन क्वीन में शिमला से कालका रवाना हो गए।

एचपीयू में विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों की सूचना देगा सैल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एचपीयू में नए सत्र से केंद्रीय करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सैल हजारों छात्रों को निजी और सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूचना और कैंपस इंटरव्यू जैसी सुविधाएं देना शुरू कर देगा। जनवरी में विवि की वित्त समिति और कार्यकारी परिषद से सेंट्रल प्लेसमेंट सैल खोलने और इसे सशक्त बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। विवि प्रशासन इसे प्रभारी ढंग से शुरू करने को लेकर कार्य योजना बना रहा है।

इस सैल के लिए दोनों निर्णायक संस्थाओं से अलग से स्टाफ रखने को पद सृजन और भर्ती के लिए भी हरी झंडी मिली है। सैल के मुखिया के रूप में विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर को जिम्मेदारी दी जाएगी। सैल के अस्तित्व में आने पर विवि के प्रोफेशनल संस्थानों में चल रहे करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सैल मर्ज हो जाएंगे। सैल के लिए विवि अलग से बजट प्रावधान भी करेगा। इसमें दो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, एक अधिकारी की भर्ती होनी है।

हर विभाग में करियर काउंसलिंग की छात्रों को मिलेगी सुविधा

यह सेंट्रल सैल विवि पीजी सेंटर में चल रहे 28 से अधिक विभागों, एमबीए, यूआईआईटी, यूसीबीएस, यूआईएलएस, विधि विभाग, एमटीए विभागों में पढ़ रहे छात्रों या पास आउट हो रहे छात्र की शैक्षणिक योग्यता सहित उपलब्ध रोजगार के अवसरों का डाटा रखने का कार्य करेगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

केन्द्र सरकार की मदद से मिड–डे मील की बढ़ेगी गुणवत्ता, राज्यों को मिलेगी ज्यादा मदद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिड–डे मील के तहत स्कूली बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने वाले राज्यों को केंद्र ने अतिरिक्त मदद देने की पेशकश की है। हालांकि इसके लिए राज्यों को उठाए गए ज़रूरी कदमों और संसाधनों का ब्यौरा देना होगा। केंद्र ने फिलहाल सभी राज्यों को 15 दिन के भीतर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र के इस कदम को स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

केन्द्र ने राज्यों से मांगा ब्यौरा

केंद्र ने इसे लेकर राज्यों से फिलहाल मिड–डे मील की गुणवत्ता को जांचने के लिए जिन बिंदुओं पर ब्यौरा देने को कहा है, उनमें अब तक बनाई रसोई, हर दिन के हिसाब से उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का मेन्यू, तिथि जैसे विशेष भोजन के साथ अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसी जानकारी देने को कहा गया है। सरकार ने इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2019–20 के लिए राज्यों से जिलेवार वार्षिक योजना और बजट का ब्यौरा भी देने को कहा है। साथ ही यह संकेत भी दिया है, वह नई सरकार के गठन से पहले इससे जुड़ी कवायद को पूरा कर लेना चाहती है।

प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान फिसला चुनाव का समय पत्रकारों के लिए बेहद खतरनाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडिया की प्रेस आजादी से संबंधित एक सालाना रिपोर्ट में भारत दो पायदान खिसक गया है। 180 देशों में भारत 140वें नंबर पर पहुंच गया है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चुनाव प्रचार का दौर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक है। चुनाव प्रचार के वक्त पत्रकार सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं।

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 यानी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' के अनुसार प्रेस की आजादी के मामले में नॉर्वे शीर्ष पर है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनियाभर में पत्रकारों के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी है। इस वजह से भारत में बीते साल अपने काम के कारण कम से कम 6 पत्रकारों की हत्या कर दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पत्रकारों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण में आरोप लगाया गया है कि 2019 के आम चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थकों द्वारा पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। हिंदुत्व को नाराज करने वाले विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणित अभियानों पर चिंता जताई है। प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान फिसलकर 140वें, पाकिस्तान 3 पायदान लुढ़ककर 142 वें और बांग्लादेश 4 पायदान लुढ़ककर 150वें स्थान पर है। नॉर्वे लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर है जबकि फिनलैंड दूसरे स्थान पर है।

तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी की पीठ पर जबरन दागा 'ॐ'

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के एक विचाराधीन कैदी ने जज के सामने अपनी टी-शर्ट उतारकर अपनी पीठ पर बना ॐ का निशान दिखाया और कहा कि यह निशान जेल निरीक्षक ने जबरन दागा है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि नब्बीर नामक इस कैदी ने मेट्रोपेलिटिन मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि जेल निरीक्षक ने गर्म धातु से उनकी पीठ पर निशान बनाया, इसके अलावा नवरात्र के दौरान दो दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया गया और उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित करने की धमकी भी दी गई।

नब्बीर को मकोका के तहत साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वे तिहाड़ की जेल नंबर 4 में बंद थे।

द रीव टाइम्स संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा

फोन न. 0177 2640761, मेलः editor@themissionriev.com

Title Code : HPBIL00313

RNI Reference No. 1328500

Sri Lanka Blast : भारत आ सकते हैं श्रीलंका के सुसाइड बॉम्बर्स, समुद्री सीमा पर अलर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय तट रक्षक के सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका के साथ लगी भारत की समुद्री सीमा को हाई-अलर्ट पर रखा गया है। जहाजों और समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट को इलाके में तैनात कर दिया गया है, ताकि श्रीलंका में आतंकी घटना के जिम्मेदार भागकर भारत की सीमा में न घुस पाएं। हालांकि, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसका शक तौदीद जमात नाम के आतंकी संगठन पर है।

इस आतंकी संगठन के तार भारत के तमिलनाडु राज्य से भी जुड़े हैं। श्रीलंका का एक कट्टरपंथी मुस्लिमों का संगठन है, जो पिछले भगवान बौद्ध की कुछ मूर्तियां तोड़ने के बाद चर्चा में आया था। लिहाजा, भारतीय सुरक्षाबलों ने एहतियान यह कदम उठाया है।

दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगने पर खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद, विपक्ष ने लगाए फाइल जलाने के आरोप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली के शास्त्री भवन में मंगलवार को आग लग गई, जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दलों के बीच "फाइलों के जलने" को लेकर बयानी जंग शुरू हो गया। हालांकि, एक अधिकारी ने बताया कि कोई भी दस्तावेज नष्ट नहीं हुआ है।दोपहर में आग लगने के बाद कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और माकपा के सीताराम येचुरी जैसे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए कि सरकारी फाइलें नष्ट की गई हैं। हालांकि, भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

क्या पीएम के हेलिकॉप्टर की जांच कर सकते हैं चुनाव अधिकारी?

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात कर्नाटक काडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।

अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मोहसिन ने 'एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों' से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और अपने 'कर्तव्य की अवहेलना' की।

मोहसिन पर ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर की जांच करने के बाद की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने पत्र में 16 अप्रैल को हुई इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया है।

बीबीसी ने जब चुनाव आयोग की प्रवक्ता शैफाली शरण से पूछा कि चुनाव आयोग के अधिकारी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के वाहनों की जांच कर सकते हैं या नहीं तो इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया।

शैफाली शरण ने बीबीसी से कहा, "इस बारे में दिशा निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हैं। फिलहाल इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।"

मोहसिन को निलंबित करने के अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मोहसिन ने 2019 के दिशानिर्देश संख्या 76 और 2014 के चुनाव निर्देशों के दिशानिर्देश संख्या 464 की अवहेलना की।

ये दिशानिर्देश चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवारों के वाहनों के इस्तेमाल से संबंधित हैं। इन्हीं के तहत किसी भी प्रत्याशी के अपने चुनाव अभियान में सरकारी वाहनों के प्रयोग पर रोक है।

19 साल की बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए दिया अपना लीवर, लोग कर रहें तारीफ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोलकाता की एक 19 साल की लड़की ने अपने लीवर का 65 फिसदी हिस्सा अपने पिता को दान कर दिया है। जो कि गंभीर लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। इसके बाद लड़की के इस काम के लिए काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया में भी इन दोनों की तस्वीर को लोग शेयर कर रहे हैं।

व्यवसायी हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर दोनों पिता और बेटी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 19 वर्ष की राखी दत्ता ने अपने पिता को अपने लीवर का 65 प्रतिशत हिस्सा दान किया है। उन्होंने लिखा कि राखी ने निशान, दर्द या भविष्य में किसी भी प्रकार के खतरे के बारे में बिना सोचे यह कदम उठाया है। एक बेटी के लिए अपने पिता का प्यार बेहद खास होता है।

जो बेटियों को बेकार समझते हैं उनके सबके लिए यह एक जवाब है। उनके द्वारा शेयर की तस्वीर को अब तक 25 हजार से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं। जबकि करीब सात हजार लोग शेयर कर चुके हैं।

कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिवसेना में शामिल हुई प्रियंका चतुर्वेदी, कहा– आत्मसम्मान के लिए ऐसा किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दोपहर करीब डेढ़ बजे वह शिवसेना में शामिल हो गईं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली।

गढ़चिरौली में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, पुलिस के 16 कमांडो शहीद

- हमला कुरखेड़ा से 6 किमी दूर कोरची मार्ग पर हुआ
- जिस बस को निशाना बनाया गया, उसमें पुलिस की सी–60 फोर्स के कमांडो सवार थे
- नक्सलियों ने इसी इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की 36 गाड़ियों में आग लगाई
- नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में 11 अप्रैल को 72: मतदान हुआ था

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मंगलवार को नक्सली हमले में पुलिस के 16 जवान शहीद हो गए। इससे पहले मंगलवार देर रात इसी इलाके में नक्सलियों ने रोड निर्माण में लगे 36 वाहनों को आग लगा दी थी। नक्सली हमला कुरखेड़ा से छह किमी दूर कोरची मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के जवान निजी बस से गढ़चिरौली की ओर जा रहे थे। यह इलाका महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर है।

शहीद जवान सी-60 फोर्स के कमांडो थे

शहीद हुए जवान पुलिस की सी-60 फोर्स के कमांडो थे। इस फोर्स में 60 जवान होते हैं। इसका गठन 1992 में गढ़चिरौली के तत्कालीन एसपी केपी रघुवंशी ने किया था। इस फोर्स के कमांडो नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ही प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल ने कहा- हम इस हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रभावित इलाके में अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगे और नुकसान ना हो।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर का नया इलाज, जड़ से खत्म होगी बीमारी?

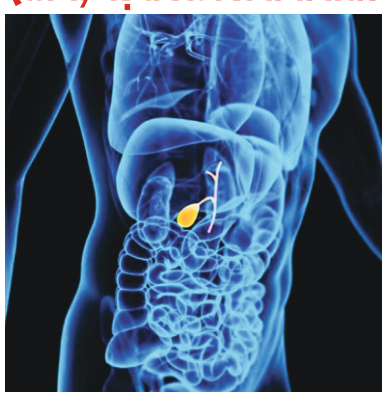

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। दुनियाभर में ये घातक बीमारी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी डाइट समेत कैंसर के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अब आप खुद को कैंसर से सुरक्षित रख सकेंगे. दरअसल, वैज्ञानिकों ने कैंसर का एक नया इलाजा ढूंढ निकाला है। वैजानिकों का दावा है कि उन्होंने डिकॉय मॉलिक्यूल्स विकसित किया है, जो कैंसर की कोशिकाओं का नष्ट करने की क्षमता रखता है।

DRI ने हैदराबाद से जब्त किया डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का गांजा, तीन लोग गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुरुवार को एक ट्रक से 1,000 किलोग्राम से अधिक मात्रा में गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 1.68 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीआरआई ने गांजा जब्त करने के साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी के मुताबिक इसे ये गांजा तस्करी के लिए आंध्रप्रदेश के सिलेरू से महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया जा रहा था।

भारतीय सेना को दिखे येति के पैर के निशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय सेना (Indian Army) ने दावा किया है कि एक अभियान दल ने हिमालय के मकालू बेस कैंप के पास मायावी हिम मानव 'येति' (Yeti) के रहस्यमय पैरों के निशान को देखा है। सेना के अतिरिक्त सूचना महानिदेशालय ने सोमवार को ट्वीट किया, 'पहली बार, भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियान दल ने मकालू बेस कैंप के करीब हिममानव 'येति' के रहस्यमयी पैरों के निशान देखे हैं। इसके साथ ही कहा था कि 'इस मायावी हिममानव को इससे पहले सिर्फ मकालू-बरुन नेशनल पार्क में देखा गया है।' मकालू-बरुन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के लिंबुवान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 26,000 फुट से अधिक उष्णकटिबंधीय वन के साथ-साथ बर्फ से ढकी चोटियां हैं। येति एक वानर जैसा प्राणी है, जो औसत मानव से बहुत अधिक लंबा और बड़ा है। यह मोटे फर में ढका हुआ होता है और माना जाता है कि यह हिमालय, साइबेरिया, मध्य और पूर्वी एशिया में रहता है। इस प्राणी को आमतौर पर एक किंवदंती के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अमेरिका मे पाक नागरिकों के वीजा पर लग सकता है प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध और कटु हो गए हैं। 26 अप्रैल को को नागरिक निर्वासन और वीजा वापसी के मामले में दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं। अमेरिका में अपने नागरिक निर्वासन और वीजा वापस लेने से इनकार करने पर अमेरिका इस्लामाबाद पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को वीजा देने से इंकार कर सकता है। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख काफी सख्त हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। इस घटना को इसी क्रम में जोड़कर देखा जा रहा है।

पाकिस्तान दुनिया के उन 10 राष्ट्रों की सूची में शामिल है, जिन पर अमेरिकी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के अनुसार इन प्रतिबंधित राष्ट्रों के नागरिकों को वीजा से अधिक रहने या वीजा वापस लेने से इंकार करने पर अमेरिकी वीजा से वंचित किया जाएगा। पाकिस्तान और घाना को ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष इस सूची में शामिल किया है। इसके पूर्व वर्ष 2001 में गुयाना, 2016 में गाम्बिया, कंबोडिया, इरिट्रिया, गिनी और 2017 में बर्मा और लाओस शामिल हैं।

अमेरिका ने वर्ष 2018 में 38 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से इंकार किया था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही अमेरिका ने वीजा कार्ड खेलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। इसी का नतीजा रहा कि पाकिस्तान को मजबूर कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। अब तक पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को फलने-फूने का पूरा मौका दे रहा था। गौरतलब है कि अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा रखी है।

इंडोनेशिया ने रामायण पर विशेष डाक टिकट किया जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2019 को रामायण की थीम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इन 70 सालों के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। इंडोनेशिया में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के अनुसार इस स्टांप का डिजाइन इंडोनेशिया के जाने-माने मूर्तिकार बपक न्योमन नुआर्ता ने तैयार किया है। डाक टिकट पर रामायण की घटना अंकित है, जिसमें जटायु सीता को बचाने के लिये बहादुरी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत-इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री अब्दुर्रहमान मोहम्मद फकीर ने हिस्सा लिया।

साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान यह तय किया गया था कि दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों को 70 साल पुरे होने पर जश्न मनाएंग। इस कार्यक्रम में साल 1949 से साल 2019 तक भारत-इंडोनेशिया संबंधों के कुछ खास पलों को प्रदर्शित करते हुए एक विशेष तस्वीर दिखाई गई।

श्रीलंका में आत्मघाती हमले, भारत ने किया पूर्व सूचना साझा करने का दावा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी कोलंबो से 40 किमी पूर्व में पुगोडा शहर में मजिस्ट्रेट अदालत के पीछे की खाली जमीन पर 25 अप्रैल को एक और ब्लास्ट हुआ। पुलिस और स्थानीय निवासियों ने इस ब्लास्ट की जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि वे विस्फोट की जांच कर रहे है। इसके बाद भी श्रीलंका मे कई स्थानों पर आतंकी हमले हुए और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच भारतीय एजेंसियों की ओर से यह भी सूचना आई कि श्रीलंका में हमलों की आशंका को लेकर वहां की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी गई थी कि इस तरह के हमले हो सकते हैं।

पहले 21 अप्रैल संडे को ईस्टर के मौके पर तीन चर्चो और तीन होटलों में हुए आत्मघाती हमलों में करीब चार सौ लोगों की मौत की सूचना है।

इस हमले की जानकारी आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) ने ली है।

वहीं, श्रीलंका सरकार ने स्वीकार किया कि देश में हुए आतंकी हमले के पीछे बड़ी विफलता रही।

अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका ने 25 अप्रैल 2019 को भारत को बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है, जिनकी वह इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा। अमेरिका के अनुसार भारत ने अपने यहां बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से निपटने की दिशा में अभी कोई उल्लेखीय सुधार नहीं किया है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधित्व (यूएसटीआर) ने अपनी रिपोर्ट में भारत सहित 11 देशों को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत एक नजर में

भारत के बारे में यूएसटीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनियों को लंबे समय से भारत में आईपी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विशेष रूप से वहां फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र के नवोन्मशकों को पेटेंट पाने और उसे कायम रखने में दिक्कतें आ रही हैं।

पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों से आवाज खोने वाले लोगों की जुबां बनेगा यह वर्चुअल यंत्र

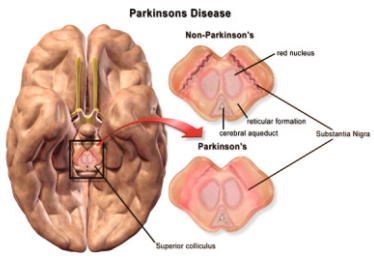

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वर्चुअल वोकल ट्रैक्ट बनाया है जो दिमाग के संकेतों से स्वाभाविक आवाज पैदा कर सकता है। इसकी मदद से ऐसे लोग बोल सकेंगे जिन्होंने किसी कारणवश अपनी आवाज खो दी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट ने ब्रेन-मशीन इंटरफेस नामक यह ट्रैक्ट तैयार किए हैं। इसकी मदद से लकवा या अन्य बीमारियों की वजह से अपनी आवाज खो देने वाले लोगों की आवाज वापस आ जाएगी। स्ट्रोक, मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने और पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्केलेरोसिस, और एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) जैसे नसों से संबंधित रोगों में अक्सर बोलने की क्षमता चली जाती है। बोलने में गंभीर रूप से असमर्थ कुछ लोग सहायक उपकरणों की मदद से अक्षरों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन यह तकनीक उतनी कारगर नहीं हैं। इससे आंखों और चेहरे की मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसके अलावा इस तरह के उपकरणों की मदद से लिखना या बोलना बहुत ही परिश्रम वाला काम होता है। इसमें ज्यादा गलती होने की संभावना रहती है। इस तकनीक के माध्यम से मुश्किल से एक मिनट में आदमी दस शब्द ही बोल पाता है, जबकि सामान्य तौर पर एक मिनट में एक व्यक्ति 100 से लेकर 150 शब्द बोलता है।

चीन से दूध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2019 को चीन से आयात होने वाले चोकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा दिया है। चीन से दूध तथा इससे जुड़ उत्पादों के आयात पर रोक अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीले रसायन मेलामीन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी।भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने चीन से दूध उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक को बंदरगाहों पर स्थिति प्रयोग शालाओं को आधुनिक बनाये जाने तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।

चीन से चॉकलेट, चॉकलेट उत्पादों, कैंडीज, कन्फैक्शनरी, दूध और दूध उत्पादों से तैयार खाद्य सामग्री के आयात पर लगी रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसी सामग्री के देश में प्रवेश वाले बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं को मेलामीन जैसे रसायन का परीक्षण करने के लिये अद्यतन नहीं बना दिया जाता है। चीन से दूध उत्पादों पर रोक तब लगाई गई थी जब उसकी कुछ दूध सामग्री में मेलामीन रसायन होने की आशंका हुई थी। मेलामीन एक खतरनाक जहरीला रसायन है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक और उर्वरक बनाने में किया जाता है।

चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर सबसे पहले सितंबर 2008 में रोक लगाई गई थी। इसके बाद से इस रोक को लगातार समय समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है। सरकार द्वारा लगाई गई इस रोक की आखिरी समयसीमा 23 अप्रैल 2019 को समाप्त हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। देश में सालाना 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान है।

ड्रग्स तस्करों के साथ तोता भी गिरफ्तार, पूछताछ में नहीं खोल रहा मुंह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वफादारी के मामले में कुत्ते से ज्यादा वफादार और भी हैं। वफादारी के मामले में कुत्ते से ज्यादा एक पक्षी भी देखा गया है। यह पक्षी और कोई नहीं, घर में पाला जाने वाला तोता है। तोता भी कुत्ते से कहीं ज्यादा वफादारी करता है, और मुसीबत आने पर मालिक के साथ खड़ा होता है।

गिरफ्तार हुआ वफादार तोता

ऐसे ही एक वफादार तोते की चर्चा ब्राजील में खूब हो रही है। उत्तरी ब्राजील में एक बेहद वफादार तोते का कारनामा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तोता अपने मालिकों के प्रति इतना वफादार निकला कि पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसने अपना मुंह तक नहीं खोला है। दरअसल, यहां ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक तोते को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के आने पर करता था अलर्ट

तस्करों (मालिकों) ने तोते को इस तरह ट्रेंड किया था कि जब भी पुलिस आती थी तो वह पुलिस-पुलिस बोलकर उन्हें अलर्ट कर देता था। पुलिस अफसरों की एक टीम ने बीते दिनो पियाउ स्टेट में ड्रग तस्कर जोड़े के यहां छापा मारा था। इस बार भी तोते ने अपने मालिकों को पुलिस-पुलिस चिल्लाकर अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए और तोता भी। पुलिस का कहना है कि अभी तक उसने कुछ बोला नहीं है, वह पूरी तरह चुप है।

अफ्रीका में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला मलेरिया का टीका, 30 वर्षों से चल रहे थे प्रयास

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया का पहला मलेरिया का टीका अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया भर में हर साल 4,35,000 को मौत के मुंह में ले जाने वाली इस जानलेवा बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए पिछले 30 वर्षों से इस टीके को लाने के प्रयास चल रहे थे। यह टीका पांच महीने से दो साल तक के बच्चों के लिए विकसित किया गया है।

दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पहल

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलावी सरकार के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी पहले अफ्रीकी महाद्वीप में दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस टीके को लाने की घोषणा की थी। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) के मौके पर इसे लाया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है।

सबसे घातक मलेरिया परजीवी के खिलाफ भी असरदार

यह टीका बच्चों के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करेगा जिससे मलेरिया के परजीवी का उन पर घातक असर नहीं होगा। यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ भी काम करता है। चिकित्सा विज्ञानी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को दुनिया भर में सबसे घातक मलेरिया का परजीवी मानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर इस परजीवी का सर्वाधिक प्रकोप है। चिकित्सकीय परीक्षणों में इस टीके से मलेरिया के 10 में से चार मामलों में बचाव देखा गया है।

सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वॉटरफॉल खुला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वॉटरफॉल 17 अप्रैल 2019 से आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया। एयरपोर्ट के एक हिस्सा पिछले करीब चार साल से नवीनीकरण किया जा रहा था। इसको नया रूप देने में करीब आठ हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। चांगी एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि यह छत के नीचे बने झरनों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई करीब 130 फुट है। एयरपोर्ट की छत पर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। यह वॉटरफॉल गुंबद के आकार वाले कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसमें चार मंजिला गार्डन और 280 से अधिक रीटेल और फूड आउटलेट्स हैं। इसमें एक वनस्पति उद्यान भी है, जिसमें 120 प्रजातियों के पौधे हैं। चांगी एयरपोर्ट पर यात्री सबसे बड़े इंडोर झरने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसे चर्चित आर्किटेक्ट मोशे सफ्दी ने डिजाइन किया है।

वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर से गायब हो रहे प्लास्टिक कचरे का पता लगाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिंद महासागर दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां से यह कचरा आखिर कहां जाता है, यह एक रहस्य है।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (यूडब्ल्यूए) के शोधकर्ताओं के अनुसार, हिंद महासागर में प्लास्टिक कचरे को मापने और उसे ट्रैक करने के लिए एक संक्षिप्त शोध किया गया है। इस अध्ययन में दल ने पाया कि दक्षिणी हिंद महासागर से प्लास्टिक समुद्र के पश्चिमी हिस्से की ओर जा रहा है, जहां से यह दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अटलांटिक महासागर में बह जाता है।

यूडब्ल्यूए की पीएचडी की छात्रा मिरिजाम वैन डेर महीन ने कहा, एशियाई मानसून प्रणाली की वजह से दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिण-पूर्व हवाएं प्रशांत और अटलांटिक महासागर की हवाओं की तुलना में अधिक तेज चलती हैं।

एक बयान में उन्होंने कहा, ये तेज हवाएं प्लास्टिक अवशेषों को पश्चिम हिंद महासागर में पश्चिम की ओर धकेलती हैं। उत्तरी हिंद महासागर में संरचना से लगता है कि बंगाल की खाड़ी में संचय हो सकता है। यह भी हो सकता है कि तैरते प्लास्टिक अंततः तटों पर जमा होते होंगे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये मानसूनी हवाओं और धारा के द्वारा बहा लिए जाते होंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- वह पूर्व सेना प्रमुख जिसको हिंद महासागरीय देश सेशल्स का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है-जरनल दलबीर सिंह सुहाग
- सुप्रीम कोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच समिति में 25 अप्रैल 2019 को जस्टिस इंदू मल्होत्रा को शामिल किया गया है- रंजन गोगोई
- बौद्धिक संपदा दिवस विश्व भर में जिस दिन को मनाया जाता है-26 अप्रैल
- भारतीय निशानेबाजों मनु भाकर व सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप के जितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता-10 मीटर
- वह देश जिसने 23 अप्रैल 2019 को कहा कि वह ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों को आगे प्रतिबंधों में छूट नहीं देने के अमेरिका के फैसले के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है- भारत
- सुप्रीम कोर्ट ने जिस बैंक को निर्देश दिया कि आरटीआई कानून के तहत यदि बैंकों को कोई छूट प्राप्त नहीं हो तो इस कानून के अंतर्गत उनकी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी मुहैया करायी जाये- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
- चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 26 अप्रैल 2019 को जिस परियोजना को लेकर ऋण जाल और क्षेत्रीय आधिपत्य जमाने जैसी वैश्विक चिंताओं को कम करने की कोशिश की- बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) परियोजना
- भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने एशियन चौंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में जो पदक जीता-स्वर्ण पदक
- बौद्धिक संपदा दिवस-2019 का मुख्य विषय है- रीच फॉर गोल्ड : आईपी एंड स्पोर्ट्स
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और जिस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी क्रमशः 1,450 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये में सरकार को बेच दी है- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- अफ्रीका के जिस देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुनियाभर में मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया- मलावी
- वैज्ञानिकों के अनुसार, जिस ग्रह पर संभावित तौर पर पहले ज्ञात भूकंप के झटकों का पता लगाया है- मंगल ग्रह
- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जिस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है- पांच वर्ष
- वह देश जिसके पत्रकार सिरिल अलमिदा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार जीता है -पाकिस्तान
- वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक-2019 के अनुसार भारत का स्थान है - 80वां
- वह स्थान जहां हाल ही में पक्षी विज्ञानियों द्वारा 'वांगी-वांगी व्हाइट आई' नामक पक्षी की खोज की गई -इंडोनेशिया
- बॉलीवुड की जिस ऐक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवॉर्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द इयर से नवाजा गया है- आहना कुमरा
- पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भारवर्ग में कजाख्स्तान के पहलवान को 12–7 से हराकर जो पदक अपने नाम किया- स्वर्ण पदक
- ईरान और जिस देश ने संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है- पाकिस्तान
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने पैसे जारी किए- 10,500 करोड़ रुपये जारी किए- दो
- वह तिथि जिस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है -24 अप्रैल
- भारत में हुई वह दुर्घटना जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 20वीं शताब्दी के प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना है - भोपाल गैस त्रासदी
- हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अगुंग इस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है-इंडोनेशिया
- वह देश जिसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर रामायण पर आधारित डाक टिकट जारी की - इंडोनेशिया
- अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इस साल 2 मई के बाद भारत समेत जितने देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा- आठ
- जिस देश में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों के बाद 22 अप्रैल 2019 की आधी रात से देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई है- श्रीलंका

- विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जिस दिन को मनाया जाता है-23 अप्रैल
- नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सौरमंडल के इस ग्रह का कोर सॉलिड है -बुध
- जापान की अन्तरिक्ष एजेंसी JAXA द्वारा बुध ग्रह के लिए छोड़े गये अंतरिक्ष अभियान का नाम है -Bepi Colombo
- वह देश जिसने हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है -यूएई
- वह टीम जिसने हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता -सर्विसेज
- वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसके नाम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने असमानता का अध्ययन करने के लिए चेयर यानी अध्ययन पीठ की स्थापना की है - अमर्त्य सेन
- वह स्थान जहां एशियन एथलेटिक्स चौंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है -दोहा
- वह भारतीय खिलाड़ी जिसने भारत को जैवलीन थ्रो में रजत पदक दिलाया- अन्नू रानी
- भारत को ICP रिपोर्ट में यह स्थान प्राप्त हुआ है - 19वां
- भारतीय नौसेना ने हाल ही में गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर इस आईएनएस युद्धपोत का जलावतरण किया है -आईएनएस इम्फाल
- गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ चुके हैं - 20
- विश्व भर में जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है - 22 अप्रैल
- भारत ने 15 अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित किस सब-सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया- निर्भय
- जिस भाषा के कवि के. सिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है- तेलुगु
- भारत और वह देश जिसके बीच बीमा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से एलिस जी वैद्यन को सम्मानित किया गया- यूके
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2010 से जिस साल के बीच भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है-2019
- भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस देश में अगले महीने होने वाले आईसीसी विश्व कप 2019 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है- इंग्लैंड
- वह स्थान जहां विश्व के सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी -कैलिफोर्निया
- वह भारतीय महिला मुक्केबाज जिन्होंने हाल ही में 54 किग्रा श्रेणी में मुक्केबाजी विश्व कप-2019 में स्वर्ण पदक जीता -मीना कुमारी
- वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जायेगा -यूएई
- फिनलैंड में हुए आम चुनावों में वह पार्टी जिसे बहुमत प्राप्त हुआ है - सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी
- वह लॉन्च व्हीकल जिसके चौथे चरण को जारी रखने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है - GSLV
- वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया -चीन
- वह महिला केन्द्रीय मंत्री जिसपर चुनाव प्रचार के दौरान गलतबयानी के कारण 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है -मेनका गांधी
- वह महासागर जहां वैज्ञानिकों ने 11 हजार मीटर की गहराई में एक ऐसे अनोखे बैक्टीरिया की खोज की है, जो तैलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है - प्रशांत महासागर
- वह सरकारी विभाग जिसने स्थानीय स्तर पर तीन महीने के भीतर जैव विविधता संबंधन समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है -एनजीटी
- वह समाचार पत्र जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए 'पुलित्जर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है - न्यूयॉर्क टाइम्स
- इन्हें हाल ही में केनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है - आर. ए. शंकरनारायणन
- वह विश्वविद्यालय जिसके प्रोफेसरों की एक टीम ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिये एंटीबायोग्रामोस्कोप नामक एक उपकरण विकसित किया है - अन्ना विश्विद्यालय
- भारत द्वारा विदेश मंत्रालय में स्थापित किया गया नया विभाग है - इंडो-पैसिफिक
- अफ्रीका का वह देश जहां गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है -घाना
- भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का नाम जिसकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार क्यूबसैट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जायेगा -केशव राघवन
- सोनी द्वारा जापान में आरंभ की गई टैक्सी सेवा का नाम है – S-Ride
- वह देश जहां वैज्ञानिकों ने 3डी प्रिंटर से एक हृदय बनाया है - इजराइल
- वह यूनिवर्सिटी जिसके वैज्ञानिकों द्वारा केपलर-47 प्रणाली में तीसरा ग्रह खोजा गया - सैन डिएगो यूनिवर्सिटी
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से चाइनीज वीडियो-शेयरिंग ऐप टिकटॉक हटा दिया गया था- मद्रास हाईकोर्ट
- वह दिग्गज गायिका जिसने फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये देने का 16 अप्रैल 2019 को घोषणा किया- लता मंगेशकर
- दक्षिणी सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) में सेवा दे रहे कुल जितने भारतीय शांतिरक्षकों को उनके बलिदान एवं समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया गया है-150
- जिस भारतीय महिला एकदिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के गुडविल एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है- मिताली राज
- वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है -मुकेश अंबानी
- भारत-वियतनाम के मध्य संपन्न हुए दूसरे नौसेनिक युद्धाभ्यास में भारत के इस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था -आईएनएस कोलकाता

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत प्रदेश को कब तक क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है- 2021
- प्रदेश के किन दो कॉलेजों को हाल ही में नैक से ए ग्रेड मिला- दो, मंडी और धर्मशाला कॉलेज
- हमीरपुर संसदीय सीट से आजाद उम्मीद्वार के तौर पर किसने जीत दर्ज की थी- आनंद चंद
- कश्मीर पर आधारित धारा 370 की शूटिंग कहां पर की गई- मनाली
- हिमाचल में कौन सी लोकसभा सीट आरक्षित है- शिमला संसदीय क्षेत्र
- किस जिले में 3200 छात्रों ने मानव श्रृखंला बनाकर मतदान करने की अपील की- कुल्लू
- ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गठित राज्य स्तरीय कमेटी का चेयरमेन किसे बनाया गया है- राजवंत संधु
- किस जिला में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 5 हजार से अधिक लोगों ने भारत का नक्शा बनाकर वोटर की अममियत बताई- ऊना
- एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुंदरनगर के किस मुक्केबाज द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया- आशीष चौधरी
- 15 अप्रैल को हिमाचल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया- 71वां स्थापना दिवस, हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था।
- मंडी जिला के किस स्थान पर वैशाखी पर्व पर पवित्र स्नान तथा मेले का आयोजन किया जाता है- रिवाल्सर
- हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों में करीब कितने मतदाता हैं-51 लाख जिनमें महिलाओं की संख्या 25 लाख के करीब है।
- हिमाचल में रूसा-3 किस वर्ष लागू किया जाना प्रस्तावित है-2020
- दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां स्थापित किया गया है- हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में टाशीगंग में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 15,256 है।
- सी विजिल एप का संबंध किससे है-चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने हेतु।
- हिमाचल में कितने आदर्श आवासीय एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे- तीन, एक चंबा के पांगी में, दूसरा भरमौर और तीसरा लाहौल स्पीति के बारिंग में।
- इससे पहले किन्नौर में के निचार में 2005 में पहला एकलव्य स्कूल खोला गया था।
- वह कौन सा दल है जिसने हिमाचल की चार संसदीय सीटों में से केवल एक पर प्रत्याशी उतारा है- सीपीआईएम, मंडी से
- मंडी में कहां पर पांच दिवसीय किसान मेले का आयोजन हाल ही में किया गया- पद्धर में
- कुल्लू जिला में कौन सी फसल स्टैफ विलियम ब्लास्ट के कारण प्रभावित हुई- लहसुन
- हाल ही में राज्य शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से घोषित दसवीं के परीक्षा परिणाम में किस छात्र ने टॉप किया- अथर्व ठाकुर
- हिमाचल में कौन से चरण में लोकसभा चुनाव आयोजित होंगे- चौथे चरण में
- भ्यूली को किसने मंडी की राजधानी बनाया- बाणसेन के पुत्र कल्याण सेन ने
- मुगल बादशाह जहांगीर किसके शासनकाल में कांगड़ा आया- जगत सिंह के
- महाभारत युद्ध में कांगड़ा के किस राजा ने कौरवों का साथ दिया था- सुशर्मा चंद्र ने
- शोनपुर कहां की राजधानी होने के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं- सिरमौर की
- किस रियासत के शासक को 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता था- बिलासपुर
- ईरान के शासक नादिरशाह ने किस राजा को बंदी बनाया था- बिलासपुर के राजा देवी चंद को
- किसे प्राचीन समय मे प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था- पठानकोट को
- अजबर सेन ने 1527 में मंडी की स्थापना की, इससे पूर्व यह क्षेत्र किसके अधिकार में था- सिंघयान के राणा गोकुल

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना

पुष्प क्रांति योजना के जरिए युवा किसान फूलों की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई हिमाचल पुष्प क्रांति योजना शुरु की गई है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।

पुष्प क्रांति योजना के तहत फूलों के उत्पादन के लिए उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस, किसानों को प्रशिक्षण और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पुष्प क्रांति योजना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के हिसाब से लोन उपलब्ध कराने की पहल भी की है। पुष्प क्रांति योजना के जरिए युवा किसान फूलों की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं।

पुष्प क्रांति योजना के तहत फूल उगाने के लिए उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस बनाने और पुष्प की खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही वित्तिय मदद दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश का वातावरण पुष्प उगाने के लिहाज से भी अनुकूल है, इस वजह से सरकार युवाओं को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। निजी क्षेत्र की पुष्प विपणन क्षेत्र में सहभागिता व कृषि संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुष्प क्रांति योजना से राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। इसमें कुशल एवं अकुशल, दोनों तरह के लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सकेंगे।

क्या है पुष्प क्रांति योजना का उद्देश्य

हिमाचल पहले ही फूलों के उपज के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सरकार प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को पुष्प की खेती के लिए आकर्षित करना चाहती है। इससे प्रदेश से पलायन रोकने और युवाओं की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। संरक्षित वातावरण में साल भर विविध किस्मों के फूल पैदा किए जा सकते हैं। फूलों की संरक्षित खेती से किसानों को मौसम से होने वाले नुकसान और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिलेगी।

फूल भेजने पर भी किराये में राहत

हिमाचल प्रदेश से फूल बसों के जरिये राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के बाजारों में भेजे जाते हैं। सरकार रोडवेज बस के किराये में पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को 25 प्रतिशत छूट दे रही है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि राज्य सरकार हिमाचल को पुष्प प्रदेश के रूप में विकसित करेगी।

पुष्पक्रांति योजना के लाभ

- पुष्प क्रांति योजना के तहत संरक्षित वातावरण में साल भर फूलों की विभिन्न किस्में उग सकती हैं
- फूलों की संरक्षित फसलों से किसानों को मौसम और जंगली जानवरों से नुकसान होने पर मदद मिलेगी
- राज्य सरकार पुष्प क्रांति योजना के लिए युवाओं को ऋण सुविधा भी देगी
- हिमाचल सरकार की तरफ से पुष्प उत्पादन के लिए उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस, किसानों को प्रशिक्षण व अन्य साधन के लिए 10 करोड़ रूपये का आंबटन

कैसे करें आवेदन

पुष्प क्रांति योजना के तहत सरकारी मदद प्राप्त करने के लिए आप अपने इलाके के बागवानी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। पुष्प क्रांति योजना में आपको संरक्षित खेती के लिए उच्च तकनीक वाले पहली हाउस बनाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। प्रदेश में पहले ही सोलन, बिलासपुर, मंडी व हमीरपुर जिला में बड़े पैमाने पर फूल उगाये जाते हैं। इसके साथ ही खेती को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार खेत संरक्षण योजना में सोलर बाड़ लगाने के लिए भी 85% तक सब्सिडी देगीं।

क्या है पॉलीहाउस तकनीक

जिन इलाके में परंपरागत खेती नहीं हो सकती, वहां इस तकनीक की मदद से फसल के उपज की संभावना बनती है। फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ जाती है। किसी भी स्थान पर सालों भर खेती संभव है। किसी भी फसल को किसी भी स्थान पर वर्ष पर्यन्त उत्पादित किया जा सकता है। बहुत कम क्षेत्र में फसलोत्पादन करके अच्छी कमाई की जा सकती है।

डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पशुधन के प्रति आकर्षित करने और दूग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2010 में दूध गंगा योजना शुरू की गई। लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब योजना को शुरू करने के लिए हरी झंडी दी, लेकिन दूध गंगा योजना का नाम बदलकर डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम रखा गया है।

हिमाचल में सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको इस योजना के तहत सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता और इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं।

2010 में शुरू की गई इस योजना में वर्ष 2014–15 में केंद्र सरकार ने काफी फेरबदल किया गया। पशुपालकों को राहत देते हुए एक लाख तक का ऋण लेने के लिए 10 प्रतिशत सीमांत राशि बैंक में जमा नहीं करवानी पड़ेगी। हिमाचल में भी पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप स्कीम को दोबारा मंजूरी मिली। अगस्त, 2013 के बाद यह स्कीम बंद हो गई थी। लेकिन फिर से इसे दोबारा शुरू किया गया।

इस योजना के मुताबिक जहां पहले दो से 10 दुधारू पशुओं के लिए पांच लाख ऋण पशुपालक ले सकते थे, वहीं अब बछड़ियों के पालन हेतु 4.80 लाख राशि को बढ़ाकर 5.30 लाख किया गया है। वर्मी कंपोस्ट के लिए 0.22 लाख, दूध दोहन मशीनों की खरीददारी के लिए 20 लाख, दूध से देशी उत्पाद बनाने के लिए 13.20 लाख, दूध उत्पादन की ढुलाई तथा कोल्ड चेन सुविधा के लिए 26.50 लाख, निजी पशु चिकित्सा ऋण के लिए 2.66 लाख और दूध व दूध उत्पादकों के शीत भंडारण के लिए किसान व पशुपालन 33.00 लाख तक का ऋण ले सकेंगे। योजना के मुताबिक अभी तक यदि किसान दो पशुओं के लिए भी ऋण लेता था तो उसको 10 प्रतिशत सीमांत राशि बैंक में जमा करवानी पड़ती थी, मगर अब यह राशि केवल वही पशुपालक जमा करवाएंगे, जो एक लाख से अधिक ऋण लेते हैं।

इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25% तथा अनुसूचित जाती व् अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33% अनुदान अन्त में समायोजित करने का प्रावधान है।

इस योजना का व्यक्ति विशेष स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, दुग्ध संगठन, दुग्ध सहकारी सभाएं, तथा कम्पनियां इत्यादि लाभ उठा सकती है।

इस परिवार के एक से ज्यादा सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग इकाइयाँ अलग-अलग स्थानों पर स्थापित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते उन के द्वारा स्थापित इकाइयों की आपस की दूरी कम से कम 500 मीटर की हो।

इन सभी मदों पर ऋणदाता को कुल ऋण की 10 प्रतिशत सीमान्त राशी अग्रिम रूप में सम्बंधित बैंक में जमा करवाई जाती है।

दुग्ध गंगा परियोजना का कार्यन्वयन नाबार्ड के सौजन्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों व् राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पशुपालन विभाग के साथ मिल कर चलाया जा रहा है।

ऋण

1.	2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए ऋण	रु॰ 05.00 लाख
2.	5 से 20 के बछडियो पालन हेतू ऋण	रु॰ 4.80 लाख
3.	वर्मी कम्पोस्ट (दुधारू गायों के इकाई के साथ जुड़ा होगा)	रु॰ 0.20 लाख
4.	दूध दोहने की मशीन मिल्कोटैस्टर बड़े दूध कूलर इकाई (2000 लीटर तक)	रु॰ 18.00 लाख
5.	दूध से देसी उत्पाद बनाने की इकाइयाँ	रु॰ 12.00 लाख
6.	दूध उत्पादों की ढुलाई तथा कोल्ड चौन सुविधा हेतु ऋण	रु॰ 24.00 लाख
7.	दूध व् दूध उत्पादों के शीत भण्डारण हेतु	रु॰ 30.00 लाख
8.	निजी पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए ऋण	
(क)	मोबाइल इकाई	रु॰ 2.40 लाख
(ख)	स्थाई इकाई	रु॰ 1.80 लाख
9.	दूध उत्पाद बेचने हेतु बूथ स्थापना	रु॰ 0.56 लाख

इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25% तथा अनुसूचित जाती व् अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ऋण पर 33.33% अनुदान अन्त में समायोजित करने का प्रावधान है।

योजना के मुख्य उदेश्य

- स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म तैयार करना
- उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने तथा उनके संरक्षण हेतु बछड़ी पालन को प्रोत्साहन देना
- असंगठित क्षेत्र में आधारभूत बदलाव लाकर दूध के आरंभिक उत्पादों को गाँव स्टार पर ही तैयार करवाना
- दूध उत्पादन के परम्परागत तरीकों को उन्नत कर व्यावसायिक स्तर पर लाना
- स्वरोजगार उत्पन्न करना तथा असंगठित डेरी क्षेत्र को मूलाधार सुविधा देना

स्वदेश दर्शन योजना

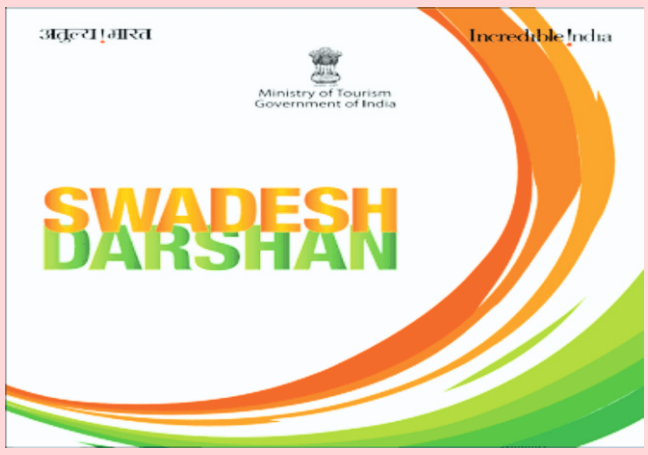

स्वदेश दर्शन योजना जनवरी, 2015 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वदेश दर्शन योजना' का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2014–15 के बजट में स्वदेश दर्शन योजना के प्रारंभ की घोषणा की गई थी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम इस बार स्वदेश योजना की जानकारी आपको दे रहे हैं।

उद्देश्य

- पर्यटन को आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के एक बड़े वाहक के रूप में स्थापित करना।
- भारत को एक वैश्विक ब्रांड तथा एक विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
- विविध थीम आधारित परिपथों एवं तीर्थस्थलों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना।
- पर्यटन आकर्षण बढ़ाने के माध्यम से समग्र पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराना।

विशेषताएं व प्रावधान

इस योजना के तहत 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई है।

ये परिपथ हैं -पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटीय परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, धरोहर परिपथ एवं ईको परिपथ।

इन परियोजनाओं की कुल लागत 2048 करोड़ रुपये है।

मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की 9 परियोजनाओं, नगालैंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्रों के लिए 3 परियोजनाओं और बिहार तथा मध्य प्रदेश में बौद्ध परिपथ हेतु 2 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2015–16 के बजट में स्वदेश दर्शन योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

पांच राज्यों में परियोजनाओं की स्वीकृति

सितंबर, 2016 में स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति द्वारा 5 राज्यों की 450 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं- मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड में विरासत परिपथ, उत्तर प्रदेश में रामायण परिपथ, सिक्किम में पूर्वोत्तर परिपथ और तमिलनाडु में तटीय परिपथ।

मध्य प्रदेश के विरासत परिपथ में 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल परियोजना लागत से 'ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडू' को कवर किया जाएगा।

उत्तराखंड के विरासत परिपथ में लगभग 83 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 'जागेश्वर-देवीधुरा-कटारमल-बैजनाथ' स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

तमिलनाडु के तटीय परिपथ में 'चेन्नई-मामल्लापुर

-रामेश्वरम-मनपदु-कन्याकुमारी' में विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की मंजूरी।

उत्तर प्रदेश के रामायण परिपथ में दो स्थलों-चित्रकूट तथा शृंगवेरपुर में लगभग 70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से विकास किया जाएगा।

सिक्किम के पूर्वोत्तर परिपथ के लिए लगभग 95.50 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इन पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाना भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीडीडी यानी NPBBDD) को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

क्या हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य

- दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण
- स्वदेशी पशु के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम
- इससे पशुओं में अनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि संभव होगी
- दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश
- साहीवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिन्धी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाना
- प्राकृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांड का वितरण
- सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2014/15 में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए थे
- 12वीं पचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है

इन कामों के लिए किया जाता है धन का आवंटन

- धन का आवंटन गोकुल मिशन के तहत एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र मसलन गोकुल ग्राम बनाना।
- उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले स्वदेशी नस्ल के संरक्षण के लिए बुल मदर फार्म्स को मजबूत करना प्रजनन तंत्र में क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग (एफपीआर यानी FPR) की स्थापना
- जर्मप्लाज्म संरक्षण संस्थानों संगठनों को मदद देना
- बड़ी आबादी के साथ स्वदेशी नस्ल के लिए वंशावरी चुनाव कार्यक्रम
- ब्रीडर्स सोसायटी, गोपालन संघ बनाना
- स्वदेशी नस्ल के कुलीन पशुओं को रखने वाले किसानों को मदद
- बछिया पालन कार्यक्रम, किसानों को पुरस्कार (गोपाल रत्न) और ब्रीडर्स सोसायटी (कामधेनु) बनाना

स्वदेशी नस्ल के लिए समय-समय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता

स्वदेशी पशु विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों में काम करने वाले तकनीकी और गैर-तकनीकि लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

गोकुल ग्राम क्या है

गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहा है और गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित है।

गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है। 1000 जानवरों की क्षमता वाले इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60:40 का है। गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाये गए हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्यों के पशुधन विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से चलाया जाता है। इस योजना के लिए फंड एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र, गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए दिया जाता है। राज्य गौसेवा आयोग को एसआईए (एलडीबी) के प्रस्ताव को प्रायोजित करने और इन प्रायोजित प्रस्तावों की निगरानी का आदेश दिया गया है। स्वदेशी पशु विभाग में सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसियों मसलन, सीसीबीएफ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि या पशुपालन विश्वविद्यालय, कहलेज, एनजीओ, सहकारी समितियां और गौशालाएं इसमें प्रतिभागी एजेंसियां हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आर्थिक उद्देश्य

गोकुल ग्राम वास्तव में एक आर्थिक संस्थान की तर्ज पर विकसित किया गया है, इसमें गौ उत्पादों की बिक्री के जरिए आर्थिक संसाधन पैदा किया जा रहा है।

दूध जैविक खाद , केंचुआ खाद, गौ मूत्र डिस्टिलेट घरेलू खपत के लिए बायो गैस से बिजली का उत्पादन, पशु उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियां गोकुल ग्राम को आत्मनिर्भर संगठन बना रही हैं।

स्त्री स्वाभिमान योजना

- महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई है। इसका नाम है स्त्री स्वाभिमान योजना। हमारे देश में आज भी कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के समय अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरुक बनाना है। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- स्त्री स्वाभिमान योजना 27 जनवरी, 2018 को लॉन्च की गई।
- स्त्री स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को ईको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन वितरित करना है।
- खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और महिलाओं को यह सैनिटरी नैपकिन बहुत ही कम मूल्य पर दिए जाते हैं।
- स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत देश में बहुत सी जगहों पर छोटी-छोटी निर्माण के लिए यूनिट्स लगाई जा रही है। इसमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल हैं।
- ऐसे में महिलाओं को इन निर्माण यूनिट में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा हैं।

लाभ

- मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी ।
- सरकारी स्कूल की सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी ।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा ।
- महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
- यह योजना देश भर तक पहुंचाई जा रही है ।

मिशन रीव : भर्तियां

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

CERTIFIED NSDC TRAINING

प्रोग्राम ऑफिसर व सर्विस एसोसिएट के पदों को भरने कि लिए
NSDC प्रमाणित प्रथम प्रशिक्षण बैच हेतु
बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं के उत्साह का स्वागत् है

आवेदन करें
www.missionriev.in
www.recruitment.missionriev.in

★ प्रशिक्षण से पहले ऑफर लेटर दिया जाएगा
★ सौ फीसद रोज़गार (प्रशिक्षण के बाद)

अगले बैच के लिए
तुरंत आवेदन करें
सीमित सीटें शेष

मात्र 25000/– रूपये प्रशिक्षण शुल्क जिसमें शामिल हैं
★ ऑनलाईन प्रशिक्षण ★ लैपटॉप/टेबलेट ★ संस्थागत प्रशिक्षण
NSDC प्रमाणित प्रमाण पत्र व रोज़गार
T&C Apply*

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
ISO 9001:2008 Certified

प्रशिक्षण शुल्क हेतु मिशन रीव देगा बैंक ऋण सहायता

For Detail Contact : 01772843528/2844073, 9816741687, 78760 52696, 82196 94079
MISSION RIEV SECRETARIAT, IIRD COMPLEX, BY PASS ROAD, SHANAN, SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH

नक्सली आतंक : 2009 से अब तक दस बड़े हमलों में 200 जवान शहीद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

28 अप्रैल, 2019 : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला में नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर हमला किया। हमले में दो पुलिस जवान शहीद हो गए तथा एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है।

19 मार्च, 2019 : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में उन्नाव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान शशिकांत तिवारी शहीद हो गए । घात लगाकर हुए इस हमले में पांच अन्य लोग घायल भी हो गए।

24 अप्रैल, 2017 : छत्तीसगढ़ के सुकमा में लंच करने को बैठे जवानों पर घातक हमला हुआ, जिसमें 25 से ज्यादा जवान शहीद हो गए।

पहली मार्च, 2017 : सुकमा जिला में अवरुद्ध सड़कों को खाली करने के काम में जुटे सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए और तीन से ज्यादा घायल हो गए।

11 मार्च, 2014 : झीरम घाटी के पास ही एक इलाके में नक्सलियों ने एक और हमला किया । इसमें 15 जवान शहीद हुए थे और एक ग्रामीण की भी इसमें मौत हो गई थी ।

12 अप्रैल, 2014 : बीजापुर और दरभा घाटी में आईईडी ब्लास्ट में पांच जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी । मरने वालों में सात मतदान कर्मी भी थे। हमले में सीआरपीएफ के पांच जवानों समेत एंबुलेंस चालक और कंपाउंडर की भी मौत हो गई थी।

दिसंबर, 2014 : सुकमा के चिंतागुफा में एंटी-नक्सल आपरेशन चला रहे सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया दिया था । नक्सलियों के इस हमले में 14 शहीद हो गए थे, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे ।

25 मई, 2013 : झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के 30 नेता व कार्यकर्ता मारे गए थे। नक्सलियों ने सबसे पहले सड़क पर ब्लास्ट किया और फिर काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी मारे गए थे, जिनमें महेंद्र कर्मा भी थे।

छह अप्रैल, 2010 : दंतेवाड़ा जिला के ताड़मेटला में यह हमला सुरक्षाकर्मियों पर हुआ। यह हमला देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला है । इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे । सीआरपीएफ के करीब 120 जवान तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी उन पर घात लगाकर करीब 1000 नक्सलियों हमला कर दिया था। इस हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में आठ नक्सली भी मारे गए थे ।

12 जुलाई, 2009 : छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस अधीक्षक वीके चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए।

हमारे सपनों का हिमाचल
MISSION RIEV-2
Ruralising India- Empowering Villages
आपके संग...हर पल...हर क्षण

मिशन रीव 2 आपकी समस्याओं का संवाहक है। इससे जुड़ने के लिए आप इसके सदस्य बनें। सदस्य बनने के बाद आपका आवश्यकता आकलन होता है जिसमें आपकी हर समस्या की मिशन रीव में ससम्मान पहचान करने के बाद रीव सेवाकर्मी इसके निदान के लिए आपके घर-द्वार पर ही सेवाऐं प्रदान करते हैं । मिशन रीव जो विश्व का अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास है....आपके सहयोग और स्नेह की छाया में सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। रोजगार और सेवा का अनूठा प्रयास...**मिशन रीव 2 से जुड़ें।**

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रबंध निदेशक
आईआईआरडी

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स
दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रूपये, छः माह के लिए 250/रूपये में और घर बैठे पाएं द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़